लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 319

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

उम्रदराज-गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों की रिहाई के लिए बने पॉलिसी... सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्य सरकारों को निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जुलाई) को जेलों में बंद कैदियों को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खास निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के कैदियों, लाइलाज या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों और शारीरिक रूप से कमजोर कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर एक पॉलिसी बनाएं।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस पॉलिसी में रिहाई पर विचार के लिए पात्रता के मानदंड और प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बेंच ने कहा कि पॉलिसी में पात्रता के लिए स्पष्ट नियम लाइलाज बीमारी की सटीक परिभाषा और एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्पक्ष स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिहाई के आवेदनों पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी आदेश दिया कि वो इस निर्देश के पालन के बारे में 6 महीने के भीतर एक हलफनामा दाखिल करें।

NALSA ने दायर की याचिका

कोर्ट ने यह फैसला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के और लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कोर्ट से कहा गया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों और लाइलाज बीमारी से पीड़ित बंदियों की रिहाई को सुगम बनाने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएं।

याचिका में कहा गया था कि लाइलाज बीमारी से पीड़ित और उम्रदराज कैदियों को विशेष चिकित्सा देखभाल तथा उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण जेल प्रशासन के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।

'तीन महीने के भीतर पॉलिसी बनाएं'

फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर उम्रदराज और/या लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों की जल्द और समयपूर्व रिहाई के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर उसे अधिसूचित करें। बेंच ने कहा कि राज्यों को अपनी नीति NALSA के साथ परामर्श करके बनानी होगी, जिससे पात्र कैदियों की पहचान और प्रक्रिया में बेहतर तालमेल हो सके।

संक्षेप

पीएम मोदी के दौरे से बदलेगा ट्रैफिक रूट, एनएच-44 पर साढ़े तीन घंटे तक नहीं चलेगा सामान्य आवागमन

जालंधर। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी 17 जुलाई को पंजाब के औद्योगिक नगर में होने वाले प्रस्तावित आगमन को लेकर शासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो और इस दौरान आम जनता को भी कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण कुमार सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:40 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे और करीब डेढ़ घंटे तक शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा और यातायात (ट्रैफिक) प्रबंधन की रणनीतियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच -44) के बेहद करीब स्थित है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यातायात में अस्थायी रूप से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। विशेष पुलिस महानिदेशक ने जनता से विशेष अपील की है कि वे 17 जुलाई, बुधवार को दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे के बीच लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पठानकोट को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच -44) पर यात्रा करने से बचें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें और प्रशासन द्वारा तय किए गए डायवर्टेड (वैकल्पिक) अंदरूनी रास्तों का ही उपयोग करें, ताकि वे किसी भी प्रकार के ट्रैफिक जाम या असुविधा से बच सकें।

राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके का पुराना पोस्ट चर्चा में, भारत जोड़ो यात्रा पर किया था तंज

नई दिल्ली, । साल 2022 में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकली 'भारत जोड़ो यात्रा' एक बार फिर देश के सियासी और सोशल मीडिया गलियारों में अचानक सुर्खियों में आ गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई इस व्यापक यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में जनसंपर्क बढ़ाना और राजनीतिक संवाद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था। कई सालों बाद इस यात्रा के दोबारा चर्चा में आने की मुख्य वजह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके का करीब चार साल पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने इस पूरी मुहिम पर तंज कसा था। दरअसल, 8 सितंबर 2022 को अभिजीत दीपके ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर एक पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा की आलोचना की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार एक साधारण ट्रैवल व्लॉग से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगी। हाल के दिनों में उनका यह पुराना बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि कभी राहुल गांधी की मुहिम का मजाक उड़ाने वाले दीपके आज खुद घिर गए हैं।

'हर जिंदगी अनमोल है', सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, नियमित मेडिकल जांच के दिए निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नियमित मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी नियमित मेडिकल जांच की जा रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या वांगचुक की सेहत की निगरानी के लिए कोई तय व्यवस्था है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी डॉक्टर प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य जांच करते हैं और उन्हें तथा उनके साथ मौजूद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी जाती है। सरकार ने यह भी कहा कि जब भी वांगचुक ने अनुमति दी, सरकारी डॉक्टरों के साथ-साथ निजी डॉक्टरों ने भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की नियमित जांच सरकारी डॉक्टरों द्वारा की जाए और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी तरह की चिकित्सीय आवश्यकता हो तो तत्काल उचित कदम उठाए जाएं। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जो भी चिकित्सीय सहायता आवश्यक होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी।

राहुल गांधी का आरोप : भाजपा ने उत्तराखंड को पेपर लीक का 'एपिसेंटर' बनाया

नई दिल्ली, एजेंसी। शुक्रवार को देहरादून में छात्रों के साथ बातचीत से पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तराखंड पेपर लीक का केंद्र बन गया है और उन्होंने युवाओं के भविष्य को नीलाम न होने देने का संकल्प लिया। गांधी ने कहा कि वह 17 जुलाई को देहरादून का दौरा कर रहे हैं क्योंकि 'देवभूमि' को पेपर लीक का केंद्र बना दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की परीक्षाओं को लेकर यहां एक 'सिस्टम' बन गया है, जिसमें पटवारी या लेखपाल जैसे पद मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि अपराधियों द्वारा तय की गई कीमतों पर हासिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल-रोधी कानून तो बनाया, लेकिन पेपर लीक होने का

सिलसिला जारी रहा। गांधी ने कहा कि कानून सिर्फ़ काग़ज़ों तक ही सीमित रहा, जबकि परीक्षा के पेपर बाज़ार में बिकते रहे। ज़रा सोचिए: एक छात्र सालों तक तैयारी करता है। वह फ़ॉर्म भरता है, फ़ीस देता है और दूर स्थित परीक्षा केंद्र तक जाता है। फिर भी, उस छात्र के लिए बनी जगह कोई और खरीद लेता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सिर्फ़ पेपर लीक नहीं, बल्कि चोरी है। उन्होंने कहा कि यह उस युवा के अधिकारों, रोज़ी-रोटी और भविष्य की चोरी है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के हर उम्मीदवार, हर छात्र और हर युवा से कहता हूँ - यह आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूँ। 17 जुलाई, देहरादून। आइए, 'छात्रों की गूंज' को एक ज़बरदस्त आवाज़ में बदल दें। गांधी ने कहा कि हम भविष्य की नीलामी नहीं होने देंगे। हम सपनों को लीक नहीं होने देंगे।

लखीमपुर खीरी हिंसा : टेनी के बेटे को क्लीन चिट, पुलिस ने कहा- सबूत नहीं

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को गवाहों को धमकाने के आरोप से जुड़े मामले में राहत मिली है। जांच एजेंसी को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। यह मामला तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई के दौरान गवाहों को कथित रूप से प्रभावित और धमकाने के आरोपों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस प्रकरण की जांच कराई गई थी। जांच पूरी होने के बाद, एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप सिद्ध करने योग्य कोई साक्ष्य नहीं पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया है कि जांच में आशीष मिश्रा या उनके पिता की इस धमकाने की घटना में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। पीड़ित बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें 15 और 16 अगस्त 2023 को गवाही न देने के लिए धमकाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195A, 506 और 120B के तहत

सीबीआई की याचिका पर बढ़ीं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को दिया फाइनल वॉर्निंग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को एक आखिरी मौका दिया। यह मौका उन्हें CBI की उस रिवीजन याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज जैन ने गौर किया कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक समेत किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। कोर्ट को बताया गया कि पहले मौका दिए जाने के बावजूद, सिर्फ़ इन तीन प्रतिवादियों ने ही अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। देरी पर ध्यान देते हुए, बेंच ने उन्हें अपना जवाब रिकॉर्ड पर लाने का एक आखिरी मौका दिया और साफ़ कर दिया कि कार्यवाही में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीख तय की गई है।

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल DP सिंह ने कोर्ट से सुनवाई जल्दी करने और मामले को जुलाई के आखिरी हफ्ते में लिस्ट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द विचार करने की ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि वह देखेगी कि क्या तारीखें पहले की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसा करना 'थोड़ा मुश्किल' लग रहा है।

मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, राम मंदिर-पेपर लीक पर उठाएगी सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वह कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरेगी। इन मुद्दों में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था का सिस्टमैटिक तौर पर खराब होना, महंगाई और विदेश नीति शामिल हैं। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि वह परिसीमन और मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को हटाने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन बिलों का, साथ ही सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कई अन्य कानूनों का भी कड़ा विरोध करेगी।

यह रणनीति कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में तय की गई। इस बैठक में कांग्रेस

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश, पी चिदंबरम, के सुरेश, नसीर हुसैन, मणिकम टैगोर, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर, शशि थरूर, मनीष तिवारी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद 'X' पर एक पोस्ट में खड़गे ने उन मुद्दों के बारे में बताया जिन्हें पार्टी सत्र के दौरान उठाएगी। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी -- आस्था के साथ धोखा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था का अंदरूनी पतन, संस्थाओं पर कब्ज़ा, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, कई घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप, कमरतोड़ महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं और रणनीतिक गलतियां, 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पर इथेनॉल ब्लेंडिंग थोपना, बेतहाशा पेड़ों की कटाई, और SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले - ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। खरगे ने कहा कि रणनीति बैठक में उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई जो लोगों के जीवन और उनकी उम्मीदों पर असर डालते हैं।

सुरंगें, सड़कें और एयरफील्ड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया जंग जीतने का मंत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बीआरओ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के तकनीक आधारित युद्धों में आधुनिक हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सड़कें, सुरंगें, एयरफील्ड और बंदरगाह भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सैन्य अभियान की सफलता के लिए मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार युद्ध की पहली लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि उस सड़क पर शुरू होती है, जो सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाती है। इसलिए सड़क बनाने वाला भी देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात सैनिक जितना ही महत्वपूर्ण है। BRO नई तकनीकों को अपनाकर विश्वस्तरीय

इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। उन्होंने अटल टनल, उमलिंग ला और सेला टनल जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया और कहा कि ये बीआरओ की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में काम करने की मिसाल हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर दूरदराज इलाके को सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत सीमा के गांवों को अब "देश के आखिरी गांव" नहीं, बल्कि "देश के पहले गांव" के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने उद्योग, शिक्षा संस्थानों और इंजीनियरों से भी अपील की कि वे नई तकनीक, रिसर्च और बेहतर निर्माण तकनीकों के जरिए देश के रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने में योगदान दें।

इस मौके पर BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि भविष्य में रणनीतिक क्षमता केवल निर्माण की गति से नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक निर्माण तकनीकों के इस्तेमाल से तय होगी। उन्होंने बताया कि BRO अब डिजिटल प्लानिंग, AI आधारित समाधान और आधुनिक मशीनों के जरिए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भर्ती प्रक्रिया के लिए दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए। इसके अलावा BRO की तीन नई प्रकाशन पुस्तिकाएं जारी की गईं और पहली बार BRO एंथम भी लॉन्च किया गया।

यूपी में 4 साल में 1 करोड़ बढ़े कांवड़िए, 10 अरब का कारोबारसावन में कैसे दौड़ती है 12 जिलों की अर्थव्यवस्था?

नई दिल्ली, एजेंसी। 30 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। साथ में दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक यात्राओं में गिनी जाने वाली कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगाजल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री या फिर यूपी के वाराणसी और प्रयागराज पहुंचेंगे। फिर वहां से वापस कई सौ किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचेंगे। अधिकांश श्रद्धालु इस यात्रा को पैदल ही पूरा करते हैं। यही वजह है इसे सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद से कांवड़ यात्रा के यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा

हुआ है। इसके चलते होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट, टेंट, पूजा सामग्री, खाने-पीने और स्थानीय व्यापार का बड़ा बाजार भी तैयार हुआ है। इसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।लखनऊ के गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज की 2024 में आई एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1000 करोड़ यानी 10 अरब से ऊपर का कारोबार जनरेट करता है।

कांवड़ यात्रा से किन्हें होता है सबसे ज्यादा फायदा

कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों खाने-पीने की दुकानों, कपड़े बेचने वालों, फल विक्रेताओं, घड़े (कांवड़) बेचने वालों दुकानदारों को खूब फायदा होता। साथ ही अधिकांश कांवड़ यात्री पैदल होते हैं। ऐसे में ढाबों पर रुकते हैं। इससे ढाबों को रिकॉर्ड मुनाफा होता है। यात्रा के दौरान खाने-पीने की दुकानों की कमाई आम दिनों की तुलना में दोगुनी-तिगुनी हो जाती है। सामान्य महीने में आमतौर पर 2 लाख रुपये का कारोबार करने वाले ढाबे कांवड़ यात्रा के दौरान 5 से 6 लाख की कमाई करते हैं।

4 साल में कांवड़ियों की संख्या में कितना इजाफा हुआ?

अनुमानितत आंकड़ों के हिसाब से साल 2025 में उत्तर प्रदेश से तकरीबन 3 .5 करोड़ श्रद्धालुओं, ने कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं, 2024 में यह संख्या 3 .5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच रही। इसके अलावा 2023 और 2022 में यूपी से कावंडियों की संख्या 2 करोड़ के आसपास रही।वहीं, पूरे देश से साल 2025 में कुल 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे। साल 2024 में करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने यात्रा की थी। साल 2023 में श्रद्धालुओं की संख्या 3 करोड़ आंकी गई थी। वहीं, साल 2022 में करीब 3 करोड़ 80 लाख श्रद्धालु पूरे देश से कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि, साल 2025 और 2023 में उसके पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई। लेकिन उसके बावजूद यह मानकर चल सकते हैं कि 4 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों में इजाफा हुआ है।

यह कमाई सिर्फ ढाबा मालिक, रास्ते में पड़ने वाले दुकानों की नहीं होती बल्कि दिहाड़ी मज़दूर भी पैसे कमाते हैं। दरअसल, कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर काम करने के लिए स्टॉफ की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जो मजदूर रोजाना छोटे-मोटे काम कर पेट पालता था, वह कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर काम करते हुए 600 रुपये तक रोजाना कमा लेता है। इसके अलावा उसे दो बार का पेटभर का खाना भी मिल जाता है।

सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टरों को?

होटल और धर्मशाला

ढाबे, रेस्टोरेंट, फल-सब्जी विक्रेता

दूध और डेयरी, पूजा सामग्री

टेंट हाउस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल स्टोर

मोबाइल चार्जिंग और रिपेयर, कपड़ा और जूता बाजार

उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सबसे ज्यादा फायदा?

अधिकांश कांवड़ यात्री हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री तक गंगाजल लेने जाते हैं। यहां तक पहुंचने के रूट में गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत जैसे शहर आते हैं। सामान्य सी बात है, अगर कांवड़ यात्री इन रास्तों से गुजरते हैं, तो इन जिलों के व्यापारियों को फायदा होगा।

दस साल बाद जौहर विश्वविद्यालय के भीतर बनी सड़क को घोषित किया गया आम रास्ता, यूनिवर्सिटी गेट पर लगाया बोर

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बनी 3.5 किमी लंबी सड़क को लोक निर्माण विभाग ने आम रास्ता घोषित कर दिया है। विभाग ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बोर्ड लगाकर सड़क को लोक निर्माण विभाग की संपत्ति बताते हुए इसे सार्वजनिक मार्ग घोषित किया है। इस सड़क के निर्माण पर 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया था। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर विश्वविद्यालय का निर्माण

जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बनी सड़क लोक निर्माण विभाग की है। इसे आम रास्ता घोषित कर दिया गया है। इसका बोर्ड भी लगा दिया गया है। अब इस सड़क से कोई भी गुजर सकता है।
-केवी सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

पूरा कराया गया। इसके बाद मई 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कराया गया। 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया।

वर्ष 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी बजट के उपयोग की शिकायत पर तत्कालीन डीएम ने नौ सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई। जांच के दौरान निजी विश्वविद्यालय में सरकारी बजट से कराए गए कार्यों के रिकॉर्ड सामने आए। तत्कालीन डीएम ने मामले को भ्रष्टाचार मानते हुए उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सरकारी बजट से बनी इस सड़क का उपयोग अब तक केवल विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में था। अब लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है। बोर्ड लगने के बाद इस सड़क से लोगों की आवाजाही शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।

जौहर विश्वविद्यालय पर लटकी तलवार, ध्वस्त होंगे 38 भवन

सपा के कद्दावर नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के उपाध्यक्ष/डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए बनाने पर अवैध मानते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिन में खुद हटा लेने और अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पूर्व आरडीए द्वारा जौहर विश्वविद्यालय को जारी नोटिस के सापेक्ष बुधवार को निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई के बाद दिया गया। इस सुनवाई के लिए विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार, अधिवक्ता तथा कुछ प्रतिनिधि आरडीए के वीसी की भूमिका निभा रहे डीएम के समक्ष पेश हुए थे। इनके जवाब और तर्कों को संतोषजनक न मानते हुए वीसी/डीएम ने 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कुल 40 भवनों वाले विश्वविद्यालय में सिर्फ मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक ही बचेंगे। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण की जांच आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आठ जुलाई को अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय और रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और अधिवक्ता बुधवार को उपस्थित हुए। इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आठ जुलाई को अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय और रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और अधिवक्ता बुधवार को उपस्थित हुए। डीएम के मुताबिक सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय सींगनखेड़ा गांव की भूमि पर बना है। 27 सितंबर-2024 से पहले आरडीए के विकास क्षेत्र में सींगनखेड़ा गांव शामिल नहीं था। इसलिए आरडीए से नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी। यह क्षेत्र नगर पालिका में भी नहीं था। निर्माण काफी पहले का है, जिसे वर्तमान नियमों के आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता। विश्वविद्यालय पक्ष की इन दलीलों को आरडीए ने स्वीकार नहीं किया। यह माना गया कि भले ही यह स्थान आरडीए या नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था लेकिन मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक के भवन का मानचित्र जिला पंचायत से पास कराया गया है, तो शेष 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत क्यों नहीं कराया गया।

लाखों रुपए खर्च के बाद भी निजी भवन में नहीं संचालित हो पाया पंचायत भवन

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार सुल्तानपुर। पिछली पंच वर्षीय योजना में प्रधान की लापरवाही से काश्तकार की खाते की जमीन में पंचायत भवन का निर्माण हो जाने के कारण अभी तक पंचायत भवन सरकारी भवन में संचालित नहीं हो सका है। अस्थाई पंचायत भवन के सहारे विकास कार्य निपटाया जा रहा है।

स्थानीय विकास खंड के सड़ांव ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 से 2021 के पंचायती वर्ष में ग्राम प्रधान पंकज सिंह द्वारा लापरवाही पूर्वक खातेदार शिव नारायण सिंह की खतौनी की जमीन में पंचायत भवन का निर्माण करा दिया। करीब 17 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन निर्मित होने के बाद काश्तकार द्वारा अपनी जमीन के बदले में ग्राम सभा की जमीन मांगी जाने लगी। काश्तकार द्वारा जमीन की अधिक मांग किए जाने के कारण गांव सभा द्वारा जमीन नहीं दी गई। इस कारण लाखों रूपये खर्च कर बनाए गए पंचायत भवन में अभी तक विभागीय कार्य शुरू नहीं हो पाया। धीरे धीरे 2021 से 2026 पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्ति की तरफ है लेकिन विभागीय लापरवाही की चलते अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका और वर्तमान प्रधान रमाशंकर पांडेय द्वारा पंचायत भवन का संचालन किराए के भवन में किया जा रहा है।इस संबंध मे जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि जमीन हस्तांतरण की फाइल राजस्व विभाग में लंबित है। जल्द ही जमीन हस्तांतरित कराकर पंचायत भवन से कार्य संपादित कराया जाएगी।

टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा, 13 ठिकानों पर की छापेमारी

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गुरुवार (16 जुलाई) को चार राज्यों में करीब 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश ATS की FIR के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी का यह धनशोधन मामला 2024 में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (यूपी-ATS) की उस FIRर आधारित है, जिसमें एक ऐसे संगठित गिरोह का जिक्र है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ कराने, उनके लिए जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद करने में संलिप्त था।

इन राज्यों में हुई रेड

राज्य पुलिस के साथ समन्वय में ईडी के लखनऊ ऑफिस की टीम द्वारा तलाशी लिए गए स्थानों में नई दिल्ली में बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, महाराष्ट्र में रायगढ़, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाने का काम कर रहा था।

वित्तीय नेटवर्क के मिले संकेत

ईडी की जांच में एक बड़े वित्तीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी फंड हासिल किया गया और फिर उसे कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयरिंग ट्रांजैक्शन के जरिए अलग-अलग जगहों पर भेजा गया।जांच में कैश निकासी और छोटी-छोटी रकम अलग-अलग लोगों तक भेजने के भी सुराग मिले हैं।

ईडी की जांच जारी

ईडी अब इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों, फंड के स्रोत और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ईडी की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

बरेली में भीषण हादसा : हाईवे पर कैंटर और स्कॉर्पियो की भिड़ंत, पंजाब के तीन लोगों की मौत, दो घायल

आर्यावर्त संवाददाता

नवाबगंज (बरेली)। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। बरेली-पीलीभीत हाईवे पर इनायतपुर गांव के पास कैंटर और स्कॉर्पियो कार की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। कार चालक समेत दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।

मृतकों की पहचान पंजाब के फतेहगढ़ जिले के भूपेंद्र कौर (62 वर्ष) और हरजीत सिंह (60 वर्ष) के रूप में हुई है। तीसरे मृतक संतोष सिंह (65 वर्ष) लुधियाना के निवासी थे। सभी मृतक और घायल पंजाब के रहने वाले थे। ये लोग लखीमपुर खीरी के पलिया से पंजाब जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त के बाद उनके परिजनों को सूचना दे दी है।

घायलों में कार चालक मुकुंद सिंह और लाडी सिंह शामिल हैं। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। कैंटर चालक मथुरापुर निवासी पंचम लाल को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कैंटर में ऑक्सीजन सिलिंडर भरे थे।

जहां हादसा हुआ, वहां पर हो रहा निर्माण कार्य

यह हादसा इनायतपुर गांव के पास हुआ, जहां हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग को वनवे कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो कार तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे कैंटर से उसकी भीषण भिड़ंत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कैंटर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक कम्पोजिट विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने निकाली स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली

सुल्तानपुर। शिक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक कम्पोजिट विद्यालय बल्दीराय के छात्र-छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। प्रधानाध्यापक सत्येन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में रैली को विद्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छात्र-छात्राएं हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर सब पढ़ें, सब बढ़ें हर बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा का अधिकार पाए तथा शिक्षा है जीवन का आधार जैसे प्रेरणादायक नारे लगाते हुए क्षेत्र की विभिन्न गलियों और मार्गों से गुजरे। छात्रो ने ढोल बजाते हुए गांवो के ग्रामीणो को बच्चो को परिषदीय विद्यालय में भेजने को उत्साहित किया कंपोजिट विद्यालय बल्दीराय के अध्यापको ने रैली के माध्यम से अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय में नामांकन कराएं और उन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजें।

पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का लिया जायजा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की। इस दौरान ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी, उनके अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एस.पी. सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि आयोग यह आकलन कर रहा है कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की भावना के अनुरूप राजनीतिक

प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न जिलों से जुटाई गई जानकारी के अनुसार पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से अधिक दिखाई दे रहा है और फिलहाल कोई गंभीर विसंगति सामने नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही लेना होगा। आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को आवश्यक सुझाव देगा।

सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर बोलते हुए आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षा को सबसे बड़ी समस्या बताया। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके विकास पर असर पड़ता है। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि सुलतानपुर आयोग का लगभग 10वां या 11वां जिला दौरा है। आयोग प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। इसके बाद तथ्यों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में शामिल सुझाव फिलहाल गोपनीय हैं, इसलिए इस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: जांच की आंच में नए किरदार...

फाइनल रिपोर्ट सौंपने में क्यों देरी कर रही एसआईटी?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। जिसके बाद कई बड़े लोग जांच के दायरे में आ सकते हैं। जांच टीम फाइनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी निष्कर्षों की दोबारा समीक्षा की जा रही है। सभी को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है।

एसआईटी ने जांच के दौरान मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, सुरक्षा प्रोटोकॉल, बैंकिंग प्रक्रिया और संबंधित लोगों के बयान

का विस्तृत परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट में केवल गिरफ्तार संविदा पर नियुक्त नकदी गिनने वाले कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि चढ़ावा प्रबंधन की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही पर भी निष्कर्ष हैं जो जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

हर पहलू की बारीकी से जांच

शुरुआत में जांच केवल चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित थी, लेकिन अब यह दान प्राप्त करने, गिनती, सुरक्षित रखने और बैंक में जमा करने की पूरी व्यवस्था की व्यापक जांच में बदल चुकी है। SIT की रिपोर्ट इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार हुई है, जिसमें हर पहलुओं का जिक्र किया गया है।

अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव का जिक्र

जांच के दौरान कई स्तर पर भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। जांच में सामने आया है कि जानकारी मिलने के बावजूद जिम्मेदार लोग इससे अनजान बने रहे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि इस कथित चोरी में शामिल कर्मचारी ट्रस्ट में बैठे वरिष्ठ लोगों के करीबी थे जिसमें अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव का नाम खासतौर पर शामिल है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव से ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों की घनिष्ठता का भा जिक्र है।

प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या था

पिछले महीने 23 जून को एसआईटी ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित तौर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा तय सुरक्षा मानकों के बार-बार उल्लंघन की बात सामने आई थी। जांच की फाइनल रिपोर्ट में जिम्मेदार किरदारों का भी जिक्र है और उनकी भूमिका भी उल्लेखनीय बताई गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं

प्रारंभिक रिपोर्ट में CCTV फुटेज, बरामदगी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर 6 संविदा नकदी गिनने वाले कर्मचारियों और 2 पर्यवेक्षी कर्मियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में इस पहलू पर भी स्पष्ट निष्कर्ष होने की बात है।

जांच की आंच में नए किरदार

एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस इन्वेस्टीगेशन का दायरा और बढ़ेगा, जिसके बाद कई नए किरदार इस जांच की आंच में आएंगे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि महज असावधानी या अनुपस्थिति, जिम्मेदारियों से मुक्त होने का बहाना नहीं हो सकते। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट की फंक्शनिंग में व्यापक लापरवाही का भी जिक्र है।

कड़ी मेहनत व लगन से यूपी एसआई में सिलेक्ट हुआ आरक्षी

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुल्तानपुर। वर्ष 2025 में हुई आरक्षी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पहली पोस्टिंग पर तैनात सिपाही ने कड़ी मेहनत व लगन से यूपी एसआई परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लिया।सिपाही की तरक्की पर थाना प्रभारी ने सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बता दे कि कुड़वार थाना पर तैनात सिपाही अभय सिंह पुत्र सूरज सिंह यादव कानपुर जिले के झिझक गांव के निवासी है। वर्ष 2025 में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में अपना स्थान बनाने वाले अभय ने मेहनत के बदौलत 2026 की यूपी एसआई परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई है।और इन्होंने 2024 में स्नातक करने के बाद पुलिस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। इनके पिता प्राइवेट नौकरी करते है और मां मुन्नी देवी गृहिणी है। परिवार के पहले व्यक्ति है जो पुलिस सेवा में है। सिपाही के यूपी एसआई परीक्षा पास करने के बाद प्रभारी निरीक्षक प्रवीण यादव व वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश यादव सहित समस्त स्टाफ ने इन्हें शुभकामना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि अभय बहुत ही मेहनती है और ड्यूटी में भी सजग है। ईमानदारी व मेहनत की वजह से इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इनकी सफलता पर हम पुलिस परिवार गर्व की महसूस कर रहे है।

नगर आयुक्त ने जोन-4 कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

भवन के नवीनीकरण और जल निकासी सुधार के दिए निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने गुरुवार को नगर निगम के जोन-4 स्थित जोनल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय भवन के नवीनीकरण, साफ-सफाई, जब्त सामान के निस्तारण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति तथा जल निकासी व्यवस्था में सुधार को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी, जोनल सेनेटरी ऑफिसर पंकज शुक्ला, अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान नगर

आयुक्त ने कार्यालय भवन की स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिशासी अभियंता को भवन के व्यापक नवीनीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने भवन के द्वितीय तल पर आधुनिक बैठक कक्ष और रिवॉर्ड रूम विकसित करने के साथ ही कार्यालय परिसर में लिफ्ट स्थापित कराने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जब्त किए गए सामान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि परिसर में रखा जब्त सामान तत्काल हटाया जाए और कार्यालय को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखा जाए, जिससे कार्यालय का वातावरण बेहतर बना रहे।निरीक्षण के दौरान उन्होंने डूडा (डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी) के काउंटर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए।साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त ने जोनल सेनेटरी ऑफिसर को कार्यालय परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में रखी जब्त पॉलीथिन को तत्काल हटाकर उसका पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारण कराने पर भी जोर दिया।निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने विनीत खंड-6 क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे नवीनीकरण कार्य के चलते नाले पर बनाए गए अस्थायी बंधे के कारण बरसात में पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। इस पर उन्होंने नगर अभियंता को निर्देश दिए कि एलडीए अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वर्षा ऋतु के दौरान उक्त अस्थायी बंधे को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।

आईजीआरएस रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम का खराब प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने मांगा स्पष्टीकरण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। जनता की शिकायतों के निस्तारण में लखनऊ नगर निगम का प्रदर्शन प्रदेश के सबसे कमजोर नगर निगमों में शामिल हो गया है। शासन की ओर से जारी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की मई 2026 की मासिक रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम प्रदेश के पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों में तीसरे स्थान पर रहा है। रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले सभी पांच नगर निगमों से स्पष्टीकरण तलब किया है।प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने खराब रैंकिंग वाले नगर निगमों के नगर आयुक्तों को पत्र जारी कर शिकायतों के निस्तारण में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो

सकी।जानकारी के अनुसार शासन प्रत्येक माह आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आधार पर नगर निगमों की रैंकिंग जारी करता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान कर उसका फोटो सहित विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसी आधार पर प्रदेश के सभी नगर निगमों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।मई 2026 की रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम सड़क, नाली, कूड़ा उठान, प्रकाश व्यवस्था और सीवर संबंधी शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। इसके चलते उसे प्रदेश के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों में तीसरा स्थान मिला।रैंकिंग में शाहजहांपुर ने पहला, झांसी ने दूसरा, अलीगढ़ ने तीसरा, फिरोजाबाद ने चौथा और आगरा ने पांचवां स्थान प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों में जगह बनाई। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों में बरेली पहले, सहारनपुर दूसरे, लखनऊ तीसरे, मथुरा चौथे और गोरखपुर पांचवें स्थान पर रहे।शासन ने स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित नगर निगमों को शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार कर आगामी रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

17 जुलाई से यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, 22 जुलाई तक कई जिलों में अच्छी बारिश के आसार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई से प्रदेश में बारिश का दौर तेज होगा और 22 जुलाई तक तराई समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे जिलों में वर्षा की गतिविधियां अधिक रहने का अनुमान है।मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के उत्तरी तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय होगा। मौसम वैज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बारिश की शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश से होगी और अगले 48 घंटों में इसका असर धीरे-धीरे मध्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चक्रवाती परिसंचरण और मानसून द्रोणी के तराई क्षेत्र की ओर बने रहने के कारण केवल पूर्वी तराई के कुछ हिस्सों में ही बारिश हो रही थी।विभाग के अनुसार 17 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि गुरुवार के लिए कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हवा में नमी अधिक रहने के कारण कई स्थानों पर उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।बुधवार को प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबेडकरनगर में 75 मिमी, हमीरपुर में 54 मिमी, मथुरा में 44 मिमी, अयोध्या में 42 मिमी और गोरखपुर में 38 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

केशवनगर में जुए के बड़े अड्डे पर मड़ियांव पुलिस की छापेमारी, छह जुआरी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मड़ियांव थाना पुलिस ने केशवनगर क्षेत्र में संचालित जुए के एक बड़े अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से जुए की फड़ पर लगी 3.05 लाख रुपये की नकदी, आरोपियों की तलाशी से बरामद 5,010 रुपये तथा 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को मड़ियांव थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि केशवनगर क्षेत्र में कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार-जीत

की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर छापेमारी की और छह लोगों को मौके से पकड़ लिया।पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी पहचान इन्द्रानगर निवासी अतुल प्रताप सिंह, हसनगंज निवासी विकास सिंह, विकासनगर निवासी अशोक यादव, खदरा निवासी मोहम्मद नौशाद, फैजुल्लागंज निवासी मोहम्मद कलीम तथा अलीगंज निवासी राहुल के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कुछ कपड़ा, लकड़ी और फर्नीचर के कारोबार से जुड़े हैं।छापेमारी के दौरान पुलिस ने जुए की फड़ पर लगी 3 लाख 5 हजार रुपये की नकदी जब्त की। इसके अलावा आरोपियों की व्यक्तिगत तलाशी में 5,010 रुपये नकद और जुआ खेलने में इस्तेमाल किए जा रहे 52 ताश के पत्ते भी बरामद किए गए।पुलिस ने सभी आरोपियों को सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत गिरफ्तार कर थाना मड़ियांव में मुकदमा संख्या 342/2026 दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी, तलाशी और बरामदगी की पूरी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की गई।मड़ियांव पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। इसके लिए अन्य थानों और जनपदों से भी विवरण मांगा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं या नहीं।इस कार्रवाई को मड़ियांव थाना पुलिस की टीम ने अंजाम दिया, जिसमें उपनिरीक्षक अशोक कुमार सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अक्षय कुमार, हेड कांस्टेबल आकाश सिंह तथा कांस्टेबल धीरज यादव और सागर शामिल रहे।

प्रदेश के आठ संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए 14 .81 करोड़ रुपये जारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले आठ राज्य संरक्षित स्मारकों के वृहद अनुरक्षण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से 14 करोड़ 81 लाख 81 हजार 200 रुपये जारी कर दिए हैं। यह धनराशि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के माध्यम से जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के खाते में जमा करा दी गई है। इन निधियों से झांसी, ललितपुर, फिरोजाबाद, शामली और लखनऊ स्थित ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि झांसी स्थित डिमरौनी गढ़ी के अनुरक्षण कार्य के लिए 3 करोड़ 46 लाख 51 हजार 520 रुपये, ललितपुर स्थित मर्दन सिंह की बैठक के लिए 1 करोड़ 42 लाख 65 हजार 860 रुपये, लक्ष्मणगढ़ मंदिर पिपराई के लिए 55 लाख 40 हजार 920 रुपये तथा रणक्षोण मंदिर धोजारी के लिए 28 लाख 55 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।उन्होंने बताया कि झांसी के ठाकुरपुरा गढ़ी के संरक्षण के लिए 4 करोड़ 88 लाख 98 हजार 80 रुपये, फिरोजाबाद जनपद के चंद्रवाड़ किले के अनुरक्षण के लिए 1 करोड़ 60 लाख 69 हजार रुपये, शामली के प्राचीन गुंबद के लिए 1 करोड़ 70 लाख 20 हजार रुपये तथा लखनऊ स्थित बड़ा शिवाला के संरक्षण के लिए 88 लाख 88 हजार रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर जैन विद्या शोध संस्थान के खाते में उपलब्ध करा दी गई है।

जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पशुओं से इंसानों में फैलने वाले जूनोटिक (ज़ूनोटिक) रोगों और उभरते पशु रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग ने राज्य के पशु चिकित्सकों के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया है। 16 और 17 जुलाई तक गोमतीनगर स्थित होटल मैरियट में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पशु चिकित्सकों की क्षमता बढ़ाकर रोगों की समय रहते पहचान, निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पशुपालन विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र कुमार पांडेय ने किया। इस अवसर पर निदेशक (प्रशासन एवं विकास) डॉ. राजेंद्र प्रसाद, निदेशक डॉ. संगीता तिवारी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले दिन जीएचएस-राइज (GHS-RISE) परियोजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण में प्रदेश के 40 जिलों से आए 80 सरकारी पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।विशेष सचिव देवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि पशु चिकित्सक असामान्य पशु रोगों की पहचान करने वाले पहले अधिकारी होते हैं। रोगों की शीघ्र पहचान, नमूना संग्रह, प्रयोगशाला जांच, निगरानी, रिपोर्टिंग, पशुपालकों को जागरूक करने तथा रोग नियंत्रण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने तथा अपने-अपने जिलों में अन्य पशु चिकित्सकों और पैरावेट कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करने का आह्वान किया।दो दिवसीय प्रशिक्षण में आईसीएआर-आईवीआरआई, आईसीएआर-बीएचयू तथा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनडीयूएटी), कुमारगंज (अयोध्या) के विशेषज्ञ विभिन्न महत्वपूर्ण रोगों पर तकनीकी सत्र ले रहे हैं। इनमें रेबीज, बर्ड फ्लू, लेप्टोस्पायरोसिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, सीसीएचएफ, एंथ्रेक्स, स्क्रब टाइफस, ग्लैंडर्स, लंपी स्किन डिजीज, ब्रूसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस और डर्माटोफाइटोसिस जैसे रोग शामिल हैं।प्रशिक्षण के दौरान रोग निगरानी, मानकीकृत केस परिभाषाएं, प्रयोगशाला जांच, जैव सुरक्षा, नमूना संग्रह, पैकिंग एवं परिवहन तथा रोग प्रकोप की जांच जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जा रही है।राज्य स्तरीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दोनों चरणों में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कुल 150 सरकारी पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान का मौका, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन बुकिंग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत किसानों के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक किसान 16 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर कृषि यंत्रों की बुकिंग करा सकते हैं।उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल ने बताया कि किसान विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर किसान कॉर्नर में उपलब्ध स्वयंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया किसान अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय, लखनऊ से संपर्क किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ के लिए), एग्रीग्रेटर, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों तथा अन्य एकल कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (सीआरएम) योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े एकल कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत तथा एकल कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

जनसुनवाई में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं

अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विद्युत, पेयजल, सीवर, सफाई, अतिक्रमण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए।जनसुनवाई में विद्युत बिल संशोधन, नए बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना, पेयजल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, सफाई और अतिक्रमण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। मंत्री ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए

संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।ए.के. शर्मा ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संवेदनशीलता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंत्री ने विशेष रूप से ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के निदेशक (वाणिज्य) ध्यान मथाई तथा निदेशक (तकनीकी) जी.डी. द्विवेदी जनसुनवाई में मौजूद रहे। मंत्री ने दोनों अधिकारियों को विद्युत संबंधी शिकायतों की मौके पर समीक्षा कर उनका स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बायोडिग्रेडेबल विकल्प उपलब्ध कराए बिना सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण रोक संभव नहीं : अमरनाथ मिश्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और लखनऊ व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा उसके व्यवहारिक विकल्पों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों और अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल और किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है।बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र प्रताप सिंह ने की। इस दौरान मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी जे.पी. मौर्य तथा लखनऊ

व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र सहित बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।बैठक की शुरुआत में डॉ. रविन्द्र प्रताप सिंह ने व्यापारियों से सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब सरकार, व्यापारी और आम नागरिक मिलकर व्यवहारिक समाधान अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा।बैठक में वरिष्ठ महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कम कीमत वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों और ठेला-रेहड़ी संचालकों द्वारा इनके बढ़ते उपयोग के कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। वहीं महामंत्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि चंद्रनगर आलमबाग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सिंगल यूज़ पॉलिथीन का पूर्ण बहिष्कार करते हुए चाय कुल्हड़ में देना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।ट्रांस गोमती अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि भूतनाथ बाजार में व्यापारियों की जागरूकता के चलते लगभग 99 प्रतिशत दुकानों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद हो चुका है। कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी ने फर्नीचर पैकिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक को निर्धारित 75 माइक्रोन मानक के अनुरूप बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न होने से व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।महामंत्री सुशील तिवारी ने कहा कि केवल व्यापारियों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को प्रतिबंधित प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों पर भी सख्ती करनी चाहिए और आम जनता को जागरूक बनाना होगा। वहीं महामंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई अक्सर औपचारिक बनकर रह जाती है, जबकि व्यापारियों को व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते।महामंत्री मनजीत सिंह दुआ ने ग्राहकों को कपड़े और जूट के थैले के उपयोग के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। प्रियंक गुप्ता ने बाजारों में होर्डिंग, बैनर और जनजागरण अभियान चलाने का सुझाव दिया। बीकेटी परिक्षेत्र महामंत्री शशि शुक्ला ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए सस्ते और व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की।वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने बायोडिग्रेडेबल पैकिंग सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जबकि निखिल रस्तोगी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। अरविंद पाठक ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाज के सभी वर्ग समान रूप से जिम्मेदार हैं और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि केवल प्रतिबंध लगाने से प्लास्टिक प्रदूषण नहीं रुकेगा। सरकार को पर्यावरण अनुकूल और किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि व्यापारी और उपभोक्ता स्वेच्छा से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करें।अपने अध्यक्षीय संबोधन में लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रभावी रोक चाहती है तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना होगा।

सुरक्षित जल भविष्य की सबसे बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को 'आने वाली पीढ़ियों हेतु सुरक्षित जलः एक सामूहिक जिम्मेदारी' विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर विशेषज्ञों ने विस्तार से अपने विचार रखे तथा जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की, जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अपर निदेशक डॉ. ए.के. गुप्ता मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता रहे। इस अवसर पर राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक डॉ. विनय कुमार सिंह तथा गृह विज्ञान विद्यापीठ की संकायाध्यक्ष प्रो. यूवी किरण भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।

अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया। प्रो. यूवी किरण ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जबकि संचालन डॉ. मोनिका शर्मा ने किया।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि जल संकट आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित भूजल दोहन और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण जल संरक्षण पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

परमाणु संयंत्र का डाटा लीक हो गया, क्या ऐसी साइबर सुरक्षा के भरोसे आगे बढ़ेगा डिजिटल इंडिया?

देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हजारों गोपनीय दस्तावेज कथित रूप से सार्वजनिक होने के बाद भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि रैनसमवेयर गिरोह ₹वर्ल्ड लीक्स₹ ने दावा किया है कि उसने संयंत्र से संबंधित 19 हजार से अधिक संवेदनशील फाइलें डार्क वेब पर जारी कर दी हैं। इन दस्तावेजों को लगभग 8 लाख 58 हजार फाइलों के उस बड़े संग्रह का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे परियोजना से जुड़े ठेकेदार रिलायंस समूह के डाटा से चुराया गया है। हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, फिर भी विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर मामला मान रहे हैं।

इस बीच, रिलायंस समूह ने मीडिया को बताया कि तीसरे पक्ष के भारतीय डाटा सेंटर प्रदाता योट्टा के सर्वर पर रखे गए उसके डाटा में आंशिक सेंधमारी हुई है। कंपनी के अनुसार सरकार को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन किस प्रकार का डाटा प्रभावित हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया। दूसरी ओर योट्टा ने कहा कि उसने 29 मई को सर्वर पर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा लिया था और संदिग्ध रैनसमवेयर को सक्रिय होने से रोक दिया गया था। बाद में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने संभावित डाटा लीक के दावे की जानकारी दी।

हम आपको बता दें कि कथित रूप से लीक हुए दस्तावेज वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 के मध्य तक के बताए जा रहे हैं। इनमें वेंटिलेशन और शीतलन प्रणालियों के इंजीनियरिंग नक्शे, साझा नियंत्रण कक्ष की रूपरेखा, उपकरणों के निरीक्षण प्रतिवेदन, आपूर्तिकर्ताओं की सूची, विक्रेताओं के प्रस्ताव, बैठकों के अभिलेख तथा बीमा संबंधी दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। अधिकांश दस्तावेज कुडनकुलम परियोजना की तीसरी और चौथी इकाई से संबंधित हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है और जिनके वर्ष 2027 तक चालू होने की संभावना है। राहत की बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें परमाणु रिएक्टर के मुख्य तंत्र की रूपरेखा शामिल नहीं है, क्योंकि वह रूस की सरकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

फिर भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जानकारी शत्रुतापूर्ण तत्वों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी हमलावर को यह जानकारी मिल जाए कि परियोजना में किन व्यक्तियों, ठेकेदारों और प्रणालियों की पहुंच कहां तक है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से परमाणु रिएक्टर पर हमला किए बिना भी उससे जुड़ी सहायक व्यवस्थाओं, आपूर्ति श्रृंखला या तीसरे पक्ष की प्रणालियों को निशाना बना सकता है। इससे परियोजना के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि संयंत्र की परिचालन प्रणाली या परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा से सीधे समझौता हुआ है। परमाणु ऊर्जा विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि संबंधित हैकर गिरोह पहले भी कई प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को निशाना बना चुका है। देखा जाये तो यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में लगभग दो करोड़ नवासी लाख खाते किसी न किसी रूप में डाटा समझौते का शिकार हुए, जिससे भारत विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा। वहीं हाल के एक औद्योगिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत भारतीय संस्थानों को यह तक जानकारी नहीं थी कि वे कभी साइबर हमले का शिकार हुए हैं या नहीं, जबकि 57 प्रतिशत संस्थानों में बुनियादी साइबर उपायों का भी अभाव है। देखा जाये तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु क्षमता और सामरिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार भी है। इस परियोजना पर किसी भी प्रकार का साइबर हमला या गोपनीय सूचनाओं का लीक होना सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आधुनिक युद्ध में साइबर क्षेत्र को भूमि, जल, वायु और अंतरिक्ष के समान ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित सूचनाओं का दुरुपयोग कर शत्रु देश या संगठित साइबर अपराधी बिना प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के भी रणनीतिक दबाव बना सकते हैं।

यूके व्यापार समझौते से प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े अवसर खुलेंगे

स्थानीय स्तर पर उगाएं, वैश्विक स्तर पर बेचें - भारतीय किसानों को 37.5 बिलियन डॉलर के ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच से फायदा होगा।

पीयूष गोयल

आज से, यूके को होने वाले भारत के लगभग सभी निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इससे हमारे छोटे व्यवसायों, किसानों, मछुआरों, नवोन्मेषकों, महिलाओं और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे, क्योंकि परिवर्तनकारी 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) आज से लागू हो रहा है। यह भारत का सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है और यह बड़ी संख्या में नौकरियों और व्यापार- अवसरों का सृजन करके समृद्धि लाएगा। इससे भारतीय निर्माताओं को धीरे-धीरे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा और हर नागरिक को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को भी तेज गति मिलेगी। व्यवसायियों में उत्साह है। उनके पास यूके को माल भेजने के लिए विस्तृत योजनाएं हैं। रत्न और आभूषण निर्यातकों को उम्मीद है कि यूके को होने वाला निर्यात अगले तीन साल या उससे भी कम समय में 230त्न बढ़कर 2.5 अरब डॉलर हो जाएगा, जबकि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकों को उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में यूके को होने वाली बिक्री लगभग दोगुनी होकर 7.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए इस समझौते से, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, लगभग 99त्न टैरिफ लाइनों पर शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसमें लगभग 100त्न व्यापार मूल्य शामिल है, जिससे भारतीय निर्यात, जो वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद पहले से ही तेज़ी से बढ़ रहा है, के लिए अपार अवसर पैदा होंगे। युवा सोच, वैश्विक अवसर– यह जन-केंद्रित एफटीए 15 जुलाई से लागू हो रहा है, जो विश्व युवा कौशल दिवस भी है। 2015 में इसी दिन पीएम मोदी ने कौशल भारत मिशन की शुरुआत की थी, जो हमारे युवाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, योगदान देने और नेतृत्व करने में सक्षम बना रहा है।

भारतीय युवाओं के लाभ के लिए, यूके ने अब तक की अपनी सबसे व्यापक सेवा-संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसमें सभी प्रमुख सेवा क्षेत्र और भारत के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण 137 उप-क्षेत्र शामिल हैं। बेहतर बाजार पहुँच और नियामक स्पष्टता से भारतीय सेवा प्रदाताओं को आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में समर्थन मिलेगा। रोज़गार के अवसर - युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि बेहतर पहुँच के साथ रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और जूते, जैविक रसायन, प्लास्टिक, वाहन कल-पुर्जे, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्र अपने कामकाज का विस्तार करेंगे। कुल मिलाकर, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करके, सीईटीए भारतीय युवाओं को जरूरी कौशल और अवसर प्रदान करेगा, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सार्थक भूमिका निभा सकें और विकास में योगदान दे सकें। सीईटीए का एक महत्वपूर्ण पहलू है, दोहरी योगदान व्यवस्था। यह ऐतिहासिक व्यवस्था, जो सीईटीए के साथ लागू हो रही है, भारतीय श्रमिकों और नियोक्ताओं को अस्थायी कार्य-भार के दौरान यूके में दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट देती है। कर्मचारियों के लिए अस्थायी विदेशी कार्य-भार पर निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से अधिक कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय स्तर पर उगाएं, वैश्विक स्तर पर बेचें - भारतीय किसानों को 37.5 बिलियन डॉलर के ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच से फायदा होगा। इससे भारतीय डेयरी उत्पादों, चाय, कॉफी, मसालों, फलों, सब्जियों, फलों के रस, मांस और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूके के लगभग 95त्न कृषि आयात भारत के लिए शुल्क-मुक्त होंगे। इस विशाल बाजार में निर्यात तीन वर्षों में 50त्न तक बढ़ सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में डेयरी, सब्जियां, सेब, खाद्य तेल, जई (ओट्स), मोटे अनाज, कुकिंग ऑयल और अन्य जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी सुरक्षा दी गई है और इन्हें संवेदनशील सूची में रखा गया है। इन वस्तुओं पर ब्रिटेन को कोई सीमा-शुल्क छूट नहीं दी गई है। ये अपवाद मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषि समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाते हैं। एसएमई – स्थानीय प्रयास, वैश्विक ताकत – पीएम मोदी ने हमेशा से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को उच्च प्राथमिकता दी है। सीईटीए में महत्वपूर्ण एसएमई क्षेत्र की मदद के लिए एक विशेष अध्याय है, 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.8त्न थी। सीईटीए कई प्रमुख प्रावधानों के साथ एसएमई की मदद करेगा, जैसे तेज सीमा-शुल्क प्रक्रिया, डिजिटल प्रणालियों और दस्तावेज रहित व्यापार को मान्यता देने और सुविधाजनक बनाने के समझौते।

बाजार तक प्राथमिक पहुंच के अलावा, एसएमई को व्यापार, शिक्षा और वित्त, डिजिटल कौशल, व्यवसायिक अवसंरचना और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर बढ़ते सहयोग का भी लाभ मिलेगा। मछुआरों के लिए बड़ी खुशी – सीईटीए से भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 28 मिलियन लोगों की आजीविका का ज़रिया है। बाज़ार तक बेहतर पहुँच और ज़्यादा निर्यात से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र के मछुआरों को लाभ होगा। इससे न सिर्फ़ भारत के मत्स्य निर्यात को मज़बूती मिलेगी, बल्कि मछुआरों की भलाई और आजीविका में भी मदद मिलेगी और तटीय इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए बड़ी जीत – यह ऐतिहासिक समझौता, जो पारंपरिक एफटीए से कहीं अधिक है, सतत और समावेशी आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अवसर और लाभ को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने महिलाओं की बाज़ार और उभरते क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने, वित्तीय समावेश और साक्षरता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने, और उनकी क्षमता और कौशल विकसित करने जैसी विभिन्न गतिविधियाँ का वादा किया है। सीईटीए सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है। यह भारत की क्षमताओं और आकांक्षाओं में विश्वास का एक वक्तव्य है। यह एक नए भारत को प्रतिबिंबित करता है, जो सिर्फ वैश्विक व्यापार में भाग ही नहीं ले रहा है, बल्कि इसे आकार देने में भी मदद कर रहा है। हमारे किसानों, मछुआरों, कामगारों, महिला उद्यमियों, एमएसएमई, पेशेवरों और युवाओं को सशक्त बनाकर, यह समझौता देश के प्रत्येक हिस्से में रह रहे हर भारतवासी को अवसर उपलब्ध कराएगा।

व्यंग्य

90 फीसदी लोगों की समस्याओं का कोई मतलब नहीं

भारत के एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वीर दास। वीर दास ने अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में एक शो किया था, जिसकी थीम उन्होंने रखी थी 'आई कम फ्रॉम टू इंडियाज'। इस शो में उन्होंने भारत के विरोधाभासों के बारे में बताया था। विरोधाभास कई स्तर पर था। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह के विरोधाभास पर उनकी टिप्पणी थी। जैसे वीर दास ने कहा कि हिंदू दिन में देवियों की पूजा करते हैं और रात में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। इस तरह की अनेक बातें थीं, जिनको लेकर भारत में खूब विवाद हुआ। वीर दास के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उनको देश विरोधी और हिंदू विरोधी बताया गया। उन पर पाबंदी लगाने की बात हुई।

यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दो भारत की तस्वीर दिखाई थी। सवाल है कि क्या देश के अंदर दो या कई पहचान, कई नाम नहीं हैं? भारत की विविधता की चर्चा होती है। लेकिन वह विविधता भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी स्तर पर है तो उसे गौरवशाली बता कर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सामाजिक या आर्थिक विषमताओं की जैसे ही कोई चर्चा करता है वैसे ही वह निशाने पर आ जाता। धार्मिक मामलों में भी विरोधाभासों की बात करें तो लोगों को बुरा लग जाता है। तभी सवाल है कि कैसे असली भारत की तस्वीर सामने आएगी? दूसरे भारत की ही तस्वीरें हर जगह दिखाई जाती हैं और उसी आधार पर दावा किया जाता है कि भारत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है।

मिसाल के तौर पर भारत में किसी से कहा जाएगा कि आर्थिक हालत बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है या आम आदमी बहुत परेशान है। तो तुरंत एक दूसरी तस्वीर पेश कर दी जाती है। यह तस्वीर दूसरे भारत की है। कहा जाता है कि अगर आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो लाखों की संख्या में आईफोन कैसे बिक रहे हैं? इन सवालों से लाजवाब करने की कोशिश होगी कि मॉल भरे हुए हैं, थिएटर भरे हुए हैं, महंगे फोन खरीदने के लिए लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, महंगी गाड़ियों के लिए एडवांस बुकिंग हो रही है और कई महीनों की वेटिंग है फिर गरीबी कहां है? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि सिवाए इसके कि दो भारत हैं। एक भारत 90 या 95 फीसदी लोगों का है, जिनका जीवन संघर्षों से भरा है। जो पांच किलो अनाज से लेकर खैरात की दूसरी योजनाओं के इंतजार में रहते हैं। यह वो आबादी है, जो किसी तरह से जीवनयापन कर रही है। इसके मुकाबले जो पहला भारत है वह पांच से 10 फीसदी लोगों का है। अगर 10 फीसदी भी मानें तो यह संख्या 14 करोड़ के आसपास होती है। इस आबादी में काम कर रहे या रिटायर हो गए सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हैं, जिनको नियमित वेतन और पेंशन मिल रहा है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले निजी पेशेवर हैं और मध्यम व बड़े कारोबारी हैं।

यह आबादी अपने आप में इतनी बड़ी है कि महंगे फोन और महंगी गाड़ियों का बाजार इनके लिए छोटा पड़ जाएगा।

यह आबादी ब्रिटेन की पूरी आबादी के ढाई गुने के बराबर है। अमेरिका की कुल आबादी के आधे से थोड़ी ही कम है। यह आबादी अगर अलग कर दी जाए तो एक खूब संपन्न और विकसित देश दिखेगा। लेकिन बाकी 90 फीसदी लोगों का क्या? क्या 10 फीसदी लोग महंगे फोन और महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं इसलिए मान लिया जाए कि 90 फीसदी लोगों की समस्याओं का कोई मतलब नहीं है! क्या यही दो भारत की वास्तविकता नहीं है?

ब्लॉग

भारत के वस्त्र उद्योग में सततता की बुनावट: भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग देश की अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और निर्यात का एक मजबूत आधार है। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2 प्रतिशत तथा विनिर्माण सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 11 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र एवं परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और विश्व निर्यात में उसकी लगभग 4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह उद्योग 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण श्रमिक शामिल हैं।

बदलते वैश्विक बाजार और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारत अब वस्त्र उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) को बढ़ावा देकर सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार जैविक रेशों, सुरक्षित रसायनों, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण-अनुकूल प्रमाणन और उत्पादों की ट्रेसबिलिटी (उत्पत्ति का पता लगाने की व्यवस्था) जैसी पहलों को प्रोत्साहित कर रही है।

क्या है चक्रीय अर्थव्यवस्था

चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, जिसमें उत्पादों और संसाधनों का अधिकतम समय तक उपयोग किया जाता है। पुराने उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग (पुरानी वस्तु को अधिक उपयोगी उत्पाद में बदलना) करके अपशिष्ट और प्रदूषण को कम किया जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और उत्पादन अधिक टिकाऊ बनता है।

भारत में वस्त्र अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा हो रहा पुनः उपयोग

भारत में हर वर्ष लगभग 78 लाख टन वस्त्र अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट कारखानों और उपभोक्ताओं से प्राप्त होता है। कुल अपशिष्ट का 70 प्रतिशत से अधिक भाग पुनः प्राप्त कर पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अपसाइक्लिंग में लगाया जाता है।

उपभोक्ता से पहले उत्पन्न होने वाले वस्त्र अपशिष्ट का लगभग 95 प्रतिशत संगठित मूल्य श्रृंखला के माध्यम से वापस उत्पादन में उपयोग किया जाता है। कताई उद्योग में लगभग पूरा अपशिष्ट पुनः उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। वहीं उपयोग के बाद फेंके गए वस्त्रों का लगभग 55 प्रतिशत लैंडफिल में जाने से बचा लिया जाता है।

यह संपूर्ण व्यवस्था देश में 40 से 45 लाख लोगों की आजीविका का आधार बनी हुई है, जिसमें महिलाओं और वंचित वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

देश के सफल वस्त्र पुनर्चक्रण मॉडल

नवी मुंबई मॉडल

नवी मुंबई के बेलापुर में देश की पहली नगर निगम आधारित वस्त्र पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थापित की गई है। यहां अब तक 30 मीट्रिक टन वस्त्र अपशिष्ट एकत्र किया गया, 25.5 मीट्रिक टन की छंटाई की गई तथा 41 हजार से अधिक उत्पाद तैयार किए गए हैं। 400 से अधिक अपसाइक्लिंग नमूने विकसित किए गए और 1.14 लाख परिवारों तक इसकी पहुंच बनी है।

पानीपत बना पुनर्चक्रण का प्रमुख केंद्र

हरियाणा का पानीपत देश का सबसे बड़ा वस्त्र पुनर्चक्रण केंद्र बन चुका है। यहां प्रतिदिन लगभग 3500 से 5250 टन वस्त्र अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है। यहां संग्रहण, छंटाई, पुनर्चक्रण और बुनाई की समग्र व्यवस्था विकसित हो चुकी है।

मंगोलपुरी का कतरन बाजार

दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित कतरन बाजार अनौपचारिक क्षेत्र के सफल पुनर्चक्रण मॉडल का उदाहरण है। यहां प्रतिदिन 10 टन से अधिक कपड़े की कतरन छांटकर पानीपत भेजी जाती है, जिससे पुनर्चक्रण उद्योग को कच्चा माल मिलता है।

जैविक रेशों और प्राकृतिक फाइबर को बढ़ावा

सरकार जैविक कपास और अन्य प्राकृतिक रेशों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से जैविक कपास सहित विभिन्न उत्पादों का प्रमाणन किया जा रहा है।

जूट-आईकेयर कार्यक्रम के जरिए वैज्ञानिक जूट खेती, बेहतर बीज और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।

न्यू एज फाइबर मिशन के अंतर्गत रेमी, सिसल, अलसी जैसे प्राकृतिक रेशों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय फाइबर योजना घरेलू फाइबर उत्पादन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित है।

खतरनाक रसायनों पर सख्ती

सरकार वस्त्र उद्योग में हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है।

भारत में बेंजिडीन आधारित रंगों और 70 प्रकार के एजो डाई पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा भारत स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर नियंत्रण की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

वस्त्र फैशन आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को हटाने की परियोजना के अंतर्गत 400 कारखानों को शामिल किया गया है। इससे लगभग 1.47 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी तथा 10,530 टन हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

हरित विनिर्माण को बढ़ावा

सरकार प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क (पीएम मित्र पार्क) योजना के माध्यम से आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र पार्क विकसित कर रही है।

इन पार्कों में—

साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र,
अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण,
वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन,
साझा अवसंरचना

जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

सात पीएम मित्र पार्कों के विकास के लिए 4445 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दिसंबर 2025 तक 27,434 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को हरित प्रोत्साहन

देश के वस्त्र उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सरकार ने रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं—

हरित निवेश एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी।

चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना के तहत संयंत्र एवं मशीनरी निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान।

कार्बन उत्सर्जन पर निगरानी

भारतीय कार्बन बाजार व्यवस्था के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को भी शामिल किया गया है। अब उद्योगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन का विवरण देना अनिवार्य होगा। निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जिनका व्यापार भी किया जा सकेगा।

वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन को नई दिशा

1 अप्रैल 2026 से लागू नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसमें उत्पादकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है तथा अपशिष्ट पृथक्करण और संसाधन पुनर्प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत वस्त्र अपशिष्ट, जैविक अवशेष और बायोमास से उन्नत हरित सामग्री विकसित करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

पर्यावरण-अनुकूल प्रमाणन और बाजार सहायता

सरकार ने इको मार्क योजना 2024 के तहत पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र उत्पादों के लिए प्रमाणन व्यवस्था शुरू की है।

साथ ही कस्तूरी कॉटन और सिल्क मार्क जैसी पहल भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित कर रही हैं।

सरकारी खरीद में पुनर्चक्रित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र समिति, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन के बीच समझौता किया गया है।

जागरूकता अभियान भी तेज

वस्त्र उद्योग में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल रेजोल्यूशन (सु.रे.), सर्कल बैक अभियान, पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सुशासन (ईएसजी) कार्यबल तथा भारत टेक्स जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

भारत टेक्स अब देश का प्रमुख वैश्विक वस्त्र आयोजन बन चुका है, जहां फाइबर से लेकर परिधान, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और सतत उत्पादन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक मंच मिलता है।

सतत भविष्य की ओर भारत

भारत की पारंपरिक संस्कृति में वस्त्रों का पुनः उपयोग, मरम्मत और संसाधनों का संरक्षण सदियों से जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अब इन्हीं परंपराओं को आधुनिक तकनीक, हरित नीतियों और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के साथ जोड़कर भारत वैश्विक वस्त्र उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मजबूत कर रहा है।

जैविक रेशों का उपयोग, सुरक्षित रसायन, स्वच्छ उत्पादन, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण-अनुकूल प्रमाणन जैसी पहलें न केवल उद्योग को अधिक टिकाऊ बना रही हैं, बल्कि रोजगार, निर्यात और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर भी सृजित कर रही हैं। आने वाले वर्षों में भारत का वस्त्र उद्योग आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन दोनों का सशक्त उदाहरण बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पत्रकार हितों की रक्षा को लेकर जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ इंडिया की वर्चुअल बैठक में अहम निर्णय

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ इंडिया की मासिक वर्चुअल बैठक का आयोजन प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें देशभर के पत्रकारों की समस्याओं, अधिकारों की रक्षा तथा संगठन की मजबूती को लेकर गंभीर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने की, जबकि संचालन राष्ट्रीय संयोजक डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव द्वारा किया गया। बैठक का शुभारंभ करते हुए डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव ने संगठन को सशक्त बनाने के साथ-साथ पत्रकारों के हितों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन हर परिस्थिति में पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. अनुराग सक्सेना ने प्रिंट, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के साथ-साथ स्वतंत्र पत्रकारों के हितों की सुरक्षा को संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलते मीडिया परिवेश में सभी वर्गों के पत्रकारों को समान अवसर और सुरक्षा मिलना आवश्यक है। बैठक में बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कुणाल भगत तथा पटना अध्यक्ष अकबर इमाम ने जानकारी दी कि पटना में जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ इंडिया का प्रदेश कार्यालय प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे स्थानीय पत्रकारों को संगठनात्मक स्तर पर बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान अजय त्रिपाठी, बी. त्रिपाठी, पिंटू, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, संतोष तिवारी, संजय सिंह, राजू नारायण, बलदेव चौधरी, मोहम्मद कादिर, आदित्य भारद्वाज, श्याम सुंदर, मृगांक शेखर सहित आधा सैकड़ा से अधिक पत्रकारों ने अपनी-अपनी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं।

क्या सगे और सौतेले दोनों बेटों से मां को मिल सकता है गुजारा भत्ता? कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मां को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत उसके सगे बेटे से भरण-पोषण मिल रहा है तो वो बाद में अपने सौतेले बेटे से भी भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।

दरअसल यह मामला एक महिला की तरफ से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा था। फैमिली कोर्ट ने पिछले साल 15 मई 2025 को महिला के सगे बेटे को अपनी मां को हर महीने 8,000 रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। हालांकि महिला इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। उसने तर्क दिया कि उसके सौतेले बेटे को भी भरण-पोषण देने के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए,क्यों कि वो भी उसके दिवंगत पति का बेटा है।

सौतेले बेटे ने किया विरोध

याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार और सौतेले बेटे की ओर से कहा गया कि जब महिला का सगा बेटा मौजूद है और उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, तब सौतेले बेटे को इस दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सौतेले बेटे ने तर्क दिया कि जहां महिला का सगा बेटा जिसके पास पर्याप्त साधन हैं पहले से ही उनका भरण-पोषण कर रहा है, ऐसे में सौतेले बेटे पर वही दायित्व थोपने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। महिला की याचिका में कोई कानूनी योग्यता न पाते हुए हाईकोर्ट ने माना कि पुनरीक्षण याचिका बिना किसी ठोस कानूनी आधार के दायर की गई थी और इसका उद्देश्य केवल सौतेले बेटे को परेशान करना था।

वहीं मंगलवार (14 जुलाई) को पारित आदेश में जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला ने कहा कि सगे बेटे से गुजारा भत्ता मिलने के बाद मां को अपना भरण-पोषण करने में अक्षम नहीं माना जा सकता, ऐसे में वो किसी अन्य व्यक्ति से गुजारा भत्ता पाने की पात्र नहीं रह जाती। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति के भरण-पोषण का दायित्व दो या अधिक व्यक्तियों पर है और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो यह कोर्ट का दायित्व होगा कि वो परिस्थितियों के मुताबिक तय करे कि किससे और कितनी राशि गुजारा भत्ते के रूप में दिलाई जाए।

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज

इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने एक महिला की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए अपने सौतेले बेटे से भी गुजारा भत्ता दिलाने की प्रार्थना की थी। फैमिली कोर्ट ने महिला के सगे बेटे को प्रति माह 8,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

महिला की दलील

महिला का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जल्दबाजी में गुजारा भत्ते की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसके सगे बेटे पर डाल दी और सौतेले बेटे को इस दायित्व से मुक्त कर दिया। कोर्ट में महिला के वकील ने दलील दी कि दोनों बेटों को गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए था।

नजदीकियां, निकाह और कत्ल, कमरे में दफन की लाश, शमशेर ने 'दुल्हन' को क्यों मारा? ये चीज सामने लाएगी असलियत

आर्यावर्त संवाददाता

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव में हुई मुफीदन (20) हत्याकांड में पुलिस वारदात की वजह तलाश रही है। जिस हिसाब से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि मृतका के प्रति आरोपी को बहुत ही आक्रोश था।

प्रेम और भागकर निकाह के डेढ़ माह बाद ही ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसकी हत्या कर दी, यह अहम सवाल है। वहीं, हत्या करके दफन किया जाना भी वह अकेले के लिए नामुमकिन है। इसमें परिवार पर लगे आरोप और भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो सकता है।

पुलिस टीम इसमें लगी है और आरोपियों का सुराग मिल चुका है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक मझारी गांव निवासी शमशेर ने डेढ़ माह पूर्व मुफीदन (20) को मुंबई से गांव लाकर निकाह किया था। शादी के कुछ दिन तक सब सही चला। इसी बीच शमशेर ने 13 जुलाई को पत्नी के गायब होने की जानकारी दी। 14 जुलाई को पुलिस छानबीन में लगी तो संदेह और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के बाद आरोपी के कमरे में उसकी चारपाई के नीचे खोदाई करके शव निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो शाम तक नहीं आई लेकिन जो लोग खोदाई के वक्त वहां मौजूद थे, उनके अनुसार लाश तेजी से सड़ रही थी और दुर्गंध बहुत तेज थी। शरीर की बात करें तो पीठ और हाथ पर चोट का निशान प्रतीत हो रहा था।

इससे यह आशंका जताई जा रही है कि मृतका ने मौत से पहले संघर्ष किया होगा। उसी मारपीट में यह चोट लगी होगी। इसी बीच कोई ऐसी चोट आई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि जिस दिन उसकी गुमशुदगी बताई जा रही है, उसी दिन उसकी हत्या भी कर दी गई है।

मोबाइल मिले तो खुले राज

हत्या के पीछे अब तक की जो वजह सामने आ रही है उसमें मृतका का किसी दूसरे से बात करना है। अब यह सच्चाई तभी सामने आएगी, जब मृतका का मोबाइल और उससे होने वाले नंबरों पर बातचीत की जानकारी ली जाए। मामूली बात वह भी कमरे के अंदर से इतनी सी बात पर हत्या कर देना किसी के गले से उतर नहीं रहा है। फोन की जांच में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और तब असलियत सामने आएगी। मृतक के परिवार की बात करें तो संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के दसया गांव निवासी मजहर की चार बेटे और दो बेटियां हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मां की बात और कपड़ों से यह प्रतीत हो रहा है कि परवरिश करने में भी दिक्कतें हैं।

कहीं कहीं यह भी शमशेर और मुफीदन के नजदीकी का कारण बना। क्योंकि पिता से मित्रता के बाद शमशेर का आना जाना अधिक हो गया था। जैसा की मृतका की मां रो-रोकर बयां कर रही थी।

यह था मामला

डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक मझारी गांव निवासी शमशेर मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। जहां उसका परिचय संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के दसया गांव निवासी मजहर से हुआ। इसके बाद उसके यहां शेमशेर का आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच धीरे-धीरे मजहर की बेटी मुफीदन (20) से शमशेर की दोस्ती हो गई।

कुछ दिनों बाद शमशेर मुफीदन को लेकर डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक मझारी गांव आ गया। जहां दोनों पक्षों की सहमति से एक जून 2026 को निकाह दोनों का निकाह हो गया। बताया जा रहा है कि निकाह के बाद दोनों में आए दिन कहासुनी होने लगी। इसी बीच शमशेर ने थाना डुमरियागंज में 13 जुलाई को तहरीर दी कि उसकी पत्नी 11 जुलाई से गायब है। पुलिस जांच में पता चला कि मामला संदिग्ध है और वह कई पहलुओं पर जांच करने लगी। इसी बीच लड़की की मां सफीदुनिशा ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी कि मेरी बेटी को दामाद शमशेर, ससुर निबर सास खुशबूनिशा ने मार डाला है और लाश को घर में ही दफन कर दिया है। इस आधार पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश यादव, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर की तलाशी ली तो कमरे की ताजी लिपाई की हुई थी, जिस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने उस जगह की खोदाई कराई, जहां लगभग 6 फुट नीचे मुफीदुन की लाश बरामद हुई।

बिलवेश्वर मंदिर से निकली जगन्नाथ यात्रा, रथ पर बैठने को लेकर विवाद, पुलिस से भिड़ी दो महिलाएं

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के सदर स्थित बिलवेश्वर मंदिर से जगन्नाथ यात्रा की आज सुबह शांतिपूर्वक शुरुआत की गई। वहीं रथ पर बैठने को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। मंदिर समिति की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रशासन धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं प्रशासनिक बैठक में यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कुछ शर्तें रखी गईं, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। हालांकि बृहस्पतिवार सुबह शांतिपूर्वक रथयात्रा शुरू हुई। इस दौरान दो महिलाओं ने रथ के आगे चल रहे श्रद्धालुओं को रोकने का पुलिस से अनुरोध किया। इस बीच हंगामा बढ़ गया। महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। महिला पुलिस ने महिलाओं को समझाबुझाकर चुप कराया। पूरे घटनाक्रम में जगन्नाथ यात्रा समीति से जुड़े पवन गोयल, गणेश अग्रवाल, नितिन बालाजी

अपनी टीम के साथ रथ से कुछ दूरी पर पूजा-अर्चना करते हुए चलते रहे।

रथ पर के बैठने को लेकर विवाद

मंदिर समिति की सचिव राशि शर्मा का आरोप है कि बैठक में प्रशासन ने कहा कि दोनों पुजारी रथ पर सवार नहीं होंगे और केवल पूजा-अर्चना ही करेंगे। उनका कहना है कि यह निर्णय बिना किसी लिखित आदेश के सुनाया गया और इससे धार्मिक परंपराओं का सम्मान प्रभावित होता है। राशि शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा मंदिर की कुर्की का आदेश पारित किया जा चुका है, प्रशासन उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने इसे सनातन धर्म की आस्था का अपमान बताया।

दूसरे पक्ष पर नहीं जताई आपत्ति

बैठक के दौरान पुजारी गणेश दत्त शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा और उनके सहयोगियों ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के यात्रा में शामिल होने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रशासन की ओर से कहा गया कि यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु का स्वागत है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण आयोजन

प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बैठक में यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। हालांकि सुबह जब यात्रा शुरू हुई तो रथ पर कोई सवार नहीं हुआ। शांतिपूर्वक यात्रा को आगे बढ़ाया गया।

'मैं पंडित हूं और वो लोग ठाकुर...' औरैया में डॉक्टर ने यमुना में लगाई छलांग, फेसबुक लाइव में पुलिस और अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर सौरभ बाजपेई के कथित तौर पर यमुना नदी में छलांग लगाने की घटना ने सनसनी फैला दी है। घटना से पहले डॉक्टर ने फेसबुक पर लगातार चार फेसबुक लाइव किए, जिनमें उन्होंने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर मारपीट करने और पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो में डॉक्टर ने कई गंभीर दावे किए हैं।

लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी निवासी डॉक्टर सौरभ बाजपेई पिछले करीब तीन वर्षों से औरैया के हरिहरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे। बुधवार उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान दावा किया कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप था कि शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचने के बाद भी पुलिस ने उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी और समझौते का दबाव बनाया गया।

लाइव वीडियो में डॉक्टर ने कुछ लोगों को नाम लेकर अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती तो उन्हें यह कदम उठाने की नौबत नहीं आती। वीडियो में उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई।

वीडियो में आत्महत्या की कही बात

सोशल मीडिया पर वायरल दूसरे वीडियो में डॉक्टर सौरभ बाजपेई नदी के पुल पर खड़े दिखाई देते हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर कहते हैं कि वह आत्महत्या करने जा रहे हैं और इसके लिए अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने अपने परिवार, विशेषकर अपने बच्चे और पिता का भी जिक्र किया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों और डॉक्टर के बयानों की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

वीडियो में डॉक्टर कहते दिख रहे हैं कि "मैं डॉक्टर सौरभ बाजपेई, राम अवतार हॉस्पिटल में काम करता हूं। डॉक्टर एस।पी। सिंह के साथ काम करता हूं। यहां डॉक्टर एस।पी। सिंह के जीजा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, गाली-गलौज की। मैं औरैया थाने गया। वहां एसएचओ ठाकुर हैं। मैं पंडित हूं, ये लोग भी ठाकुर हैं। एसएचओ ने मामला समझौता कराने की कोशिश की।" सौरभ ने वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कठोर शब्द कहे हैं। वह कहते हैं, "मैं सुसाइड करूंगा। आज ये लोग मुझे नहीं निकलने देंगे। मुझे बंद करके रखा है, कल निकलने देंगे। मैं एक वादा कर रहा हूं, मैं सुसाइड करूंगा और मेरे सुसाइड के जिम्मेदार होंगे सवेंश सिंह और सवेंश सिंह का बेटा गौरव सिंह।"

यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन जारी

डॉक्टर के कथित तौर पर यमुना नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। देर शाम तक नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन डॉक्टर का कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

पुलिस का क्या कहना है?

क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि डॉक्टर सौरभ बाजपेई ने यमुना नदी में छलांग लगा दी है। प्रारंभिक जांच में अस्पताल के स्टाफ के साथ विवाद की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वायरल वीडियो और डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

परिजनों ने उठाए सवाल

उधर, डॉक्टर सौरभ बाजपेई के बड़े भाई अतुल बाजपेई ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके भाई के साथ अस्पताल में मारपीट हुई थी और शिकायत के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पुलिस ने तत्काल कदम उठाया होता तो शायद यह घटना नहीं होती। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने की मांग की है।

बिजली गुल हुई तो गर्मी से राहत पाने रामगंगा नदी पहुंचे 4 दोस्त, नहाते समय आंखों के सामने डूब गया आसिफ, मदद के लिए चिल्लाता रहा

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा नदी में नहाने गए चार दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के 'मोरा की मिलक' इलाके के पास रामगंगा नदी में नहाते समय चारों युवक तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस दौरान तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि चौथा युवक आसिफ नदी के गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर सिविल लाइंस थाना पुलिस, सीओ सिविल लाइंस और पीएसी के गोताखोरों की टीम पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान में जुट गई। डूबने वाले युवक की पहचान अमरोहा निवासी आसिफ के रूप में हुई है। वह शादीशुदा था और

उसकी एक छोटी बच्ची भी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। चारों युवक मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित मोनू अलमारी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। बुधवार को फैक्ट्री में बिजली नहीं होने के कारण कामकाज प्रभावित था और भीषण गर्मी व उमस से परेशान होकर चारों दोस्तों ने पास बह रही रामगंगा नदी में नहाने का फैसला किया। दोपहर के समय सभी नदी में उतरे, लेकिन उन्हें नदी के तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में चारों युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए और डूबने लगे। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मदद के लिए शोर सुनाई दिया।

हादसे के दौरान दो युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए काफी दूर तक तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। वहीं तीसरे युवक को डूबता देख मौके पर मौजूद सिविल लाइंस थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि चौथा युवक आसिफ तेज बहाव में बहकर गहरे पानी में समा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पीएसी की विशेष गोताखोर टीम को बुलाया, जिसने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खबर लिखे जाने तक आसिफ की तलाश जारी थी।

पुलिस और गोताखोरों का रेस्क्यू अभियान जारी

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिविल लाइंस, थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीएसी के प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। अधिकारियों का कहना है कि आसिफ की तलाश लगातार जारी है और उसे खोजने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में तेज बहाव वाली नदियों में नहाने से बचें, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। यह हादसा एक बार फिर नदियों में सुरक्षा बरतने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

साथी तसव्वुर खान ने सुनाई आपबीती

हादसे से सुरक्षित बाहर निकले आसिफ के साथी तसव्वुर खान ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी लोग मोनू अलमारी फैक्ट्री में काम करते हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने आए थे। वे नदी के एक किनारे से उतरकर धीरे-धीरे पुल के नीचे तक पहुंच गए थे। तसव्वुर के मुताबिक, अचानक आसिफ गहरे पानी में चला गया और मदद के लिए आवाज लगाने लगा। तसव्वुर तैरना जानता था, इसलिए उसने बिना देर किए उसे बचाने की कोशिश की। उसने आसिफ को पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वह उसे बचा नहीं सका। देखते ही देखते आसिफ उसकी आंखों के सामने पानी में लापता हो गया।

जुलूस ए बिसवां में तुराबखानी में उमड़ी भीड़

सुलतानपुर। अंजुमन पंजतनी तुराबखानी की तरफ से 15 जुलाई 2026 को बड़ा इमामबाड़ा जैनबिया तुराब खानी में रात 8बजे एक मजलिस का आयोजन किया गया। जिसको मौलाना सैयद हसन अख्तर आब्दी नौगवां सादात ने पढ़ी उसके बाद शबीह ताबूत हज़रत इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम निकाला गयासुद्दीन और जुलूस ए बीसवां उठकर मस्जिद होते हुए गंजेशहीदा पर लाकर समाप्त किया गया। दौरान जुलूस मुकामी अंजुमनों के अलावा बाहरी अंजुमन हाशमिया इलाहाबाद अंजुमन आरफी बघरा मुजफ्फरनगर ने नौहा ख्वानी व मातम किया। और तकरीर मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी मुजफ्फरनगर मौलाना शारिब अब्बास अकबरपुर ने तकरीर की संचालन मौलाना जीशान आजमी ने किया अन्त में गंजे शहीदा में कर्बला के शहीदों के लाशों को बनी असद के जरिए दफ़न की मंजर कशी की गयी इस जुलूस में सुल्तानपुर जनपद के अलावा अन्य जनपदों के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया।

इश्क में मिला धोखा, अपनों ने भी फेरा मुंह तो नारी निकेतन ने संभाला... अब कहां जाएं नहीं पता, रुला देंगी बेसहारा बेटियों की कहानियां

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। प्यार में साथ जीने-मरने के वादे, शादी के हसीन सपने और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर घर की दहलीज लांघने वाली कई युवतियों का सफर बरेली के नारी निकेतन और वन स्टॉप सेंटर पर आकर ठहर गया है। यहां रह रही कई बेटियों की कहानियां इतनी दर्दनाक हैं कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी आज इन लड़कियों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा है कि वे अब यहाँ से बाहर निकलकर कहां जाएं और किसे अपना कहें।

नारी निकेतन की चारदीवारी के पीछे रह रही एक युवती असम की रहने वाली है, जिसकी दास्तान इंसानियत को शर्मसार करती है। वो अपने प्रेमी के झूठे जाल में फंसकर अपना पूरा परिवार और राज्य छोड़कर बरेली चली आई थी।

चंद दिनों तक साथ रखने के बाद उस हैवान प्रेमी ने युवती का सौदा किसी अन्य व्यक्ति से कर दिया और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने किसी तरह युवती को रेस्क्यू कर नारी निकेतन पहुंचाया। अब वह पिछले कई महीनों से अदालती आदेश के इंतजार में दिन काट रही है, लेकिन उसे डर है कि बाहर की दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है।

NEET की तैयारी कर रही छात्रा भी हुई शिकार

एक अन्य मामला पीलीभीत की रहने वाली एक मेधावी छात्रा का है, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट (NEET) की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही वह बरेली के एक युवक के संपर्क में आई। युवक ने शादी का झांसा देकर उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन जब शादी की बात आई, तो उसने समाज और परिवार की प्रतिष्ठा का बहाना बनाकर पैर पीछे खींच लिए। समाज और परिवार के डर से युवती में घर लौटने का साहस नहीं बचा, जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट मैरिज के बाद मिला धोखा, बिखर गए सपने

दिल्ली और लखनऊ की दो अन्य युवतियों की कहानियां भी कम दर्दनाक नहीं हैं, जो रिश्तों के खोखलेपन को बयां करती हैं। दिल्ली की एक युवती ने बरेली के युवक से बकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही युवती गर्भवती हुई, बात परिवारों तक पहुंच गई। परिवार के दबाव में आकर पति ने उससे दूरी बना ली। फिलहाल, वन स्टॉप सेंटर में दोनों पक्षों की काउंसलिंग चल रही है। लखनऊ की एक अन्य युवती, जिसके माता-पिता अलग हो चुके थे, अकेलेपन के कारण एक युवक के झांसे में आकर घर छोड़ बैठी। वह अब नारी निकेतन में है। उसका कहना है कि सगी मां तो कभी मिलने भी नहीं आती, लेकिन केंद्र की अधीक्षिका में उसे मां जैसा अपनापन मिलता है, इसलिए वह अब घर नहीं जाना चाहती।

प्रशासन कर रहा पुनर्वास की कोशिश

इन बेसहारा हो चुकी बेटियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) मोनिका राणा ने बताया कि आश्रय गृह में आने वाली प्रत्येक युवती की मानसिक काउंसलिंग की जाती है। उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें दोबारा सुरक्षित माहौल दिलाने का प्रयास किया जाता है। कई मामलों में परिवार लड़कियों को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं, जिससे चुनौती बढ़ जाती है। प्रशासन न्यायालय के आदेश और स्वयं युवती की लिखित सहमति के बाद ही उनके सुरक्षित पुनर्वास की अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फर्क? लोग हो जाते हैं कंफ्यूज

हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फर्क है। इस मौके पर चलिए आपको इनके बीच का फर्क बताते हैं।

स्तन

प्लास्टिक सर्जरी का भारत में ट्रेंड बना हुआ है। एक समय था जब फिल्मी सितारे ही इसे करवाते थे। आजकल आम लोग भी इसे करवाते हैं, पर आज भी इसको लेकर अलग-अलग तरह की कंफ्यून या मिथक बने रहते हैं। दरअसल, जब भी किसी के चेहरे या शरीर में बदलाव लाने वाली सर्जरी की बात होती है, तो ज्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को एक ही समझ लेते हैं।

हालांकि, दोनों का उद्देश्य और इस्तेमाल अलग-अलग होता है। दोनों सर्जरी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती हैं। लेकिन इनके पीछे की जरूरत और लक्ष्य अलग होते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है।

क्या होती है प्लास्टिक सर्जरी?

डॉ। चिरायु परवाल (कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी विभाग, आकाश हेल्थकेयर) बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य शरीर के किसी हिस्से की मरम्मत करना या उसकी कार्यक्षमता और सामान्य बनावट को वापस लाना होता है। यह उन लोगों के लिए की जाती है, जिनका शरीर किसी दुर्घटना, जलने, जन्मजात विकार, संक्रमण या कैंसर की सर्जरी के कारण प्रभावित हुआ हो।

एग्जांपल के लिए

सड़क दुर्घटना में चेहरे की हड्डियां टूट जाना
जलने के बाद त्वचा खराब हो जाना
कटे हुए हाथ या उंगली की मरम्मत
जन्म से कटे होंठ या तालू

कैंसर के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन

ऐसी सिचुएशन में प्लास्टिक सर्जरी मरीज की नॉर्मल लाइफ और कॉन्फिडेंस दोनों लौटाने में मदद करती है।

क्या होती है कॉस्मेटिक सर्जरी?

कॉस्मेटिक सर्जरी का उद्देश्य किसी व्यक्ति की दिखावट को बेहतर बनाना होता है। इसमें शरीर का कोई हिस्सा सामान्य रूप से काम कर रहा होता है, लेकिन व्यक्ति उसे ज्यादा अट्रैक्टिव या अपनी पसंद के अनुसार बदलना चाहता है।

कॉस्मेटिक सर्जरी के कुछ आम उदाहरण

नाक की शेप बदलना
फेसलिफ्ट
लिपोसक्शन
बोटॉक्स और फिलर्स
ब्रेस्ट का आकार बढ़ाना या कम करना

पलकों की सर्जरी

इस तरह की सर्जरी पूरी तरह व्यक्ति की इच्छा और सौंदर्य संबंधी जरूरत पर आधारित होती है।

दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है?

दरअसल, प्लास्टिक सर्जरी जरूरत के लिए होती है। वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी सुंदरता बढ़ाने के लिए होती है। हालांकि, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो दोनों लिस्ट में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी हादसे के बाद नाक की सर्जरी की जाती है तो वह प्लास्टिक (रिकंस्ट्रक्टिव) सर्जरी है, लेकिन सिर्फ नाक की शेप बेहतर करने के लिए सर्जरी कराई जाती है, तो वह कॉस्मेटिक कहलाती है।

क्या कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी तरह सुरक्षित होती है?

हर सर्जरी की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी में भी कुछ जोखिम होते हैं। इंफेक्शन, ब्लड का बहना, एनेस्थीसिया से जुड़ी समस्याएं, निशान (Scar) या मन मुताबिक रिजल्ट न मिलना जैसी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए किसी भी प्रोसेस से पहले काबिल और अनुभवी प्लास्टिक सर्जन से सलाह लेना जरूरी है।

सर्जरी कराने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

सिर्फ बोर्ड-सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से ही ट्रीटमेंट कराएं।

अपनी हेल्थ सिचुएशन और मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को जरूर बताएं।

सोशल मीडिया या सेलिब्रिटी की तस्वीरों को देखकर अवास्तविक उम्मीदें न रखें।

सर्जरी के फायदे, जोखिम और रिकवरी के बारे में पहले अच्छी तरह समझ लें।

सर्जरी के बाद डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें।

आरओ के पानी से जुड़े बड़े मिथकों की जानिए सच्चाई, दूर होगी गलतफहमी

जानें

आजकल ज्यादातर घरों में पीने के लिए आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) वॉटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी से अशुद्धियों और कुछ हानिकारक तत्वों को हटाकर उसे पीने योग्य बनाना होता है। हालांकि, आरओ के पानी को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें और दावे भी सुनने को मिलते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इससे जुड़ी कई जानकारियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से लोगों में अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती है।

कुछ लोग मानते हैं कि आरओ का पानी सेहत के लिए हमेशा सबसे अच्छा होता है, जबकि कुछ का दावा है कि इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन-सी बातें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं और कौन-सी सिर्फ मिथक हैं। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय सोर्स और विशेषज्ञों की राय जानना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि आरओ के पानी से जुड़े कौन-से आम मिथक लोगों के बीच प्रचलित हैं, उनकी सच्चाई क्या है और आरओ का पानी इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आरओ के पानी से जुड़े 4 बड़े मिथक, क्या है सच्चाई

मिथक 1: आरओ का पानी पीने से शरीर में सभी मिनरल्स की कमी हो जाती है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आरओ जैसी प्रक्रियाओं से पानी में मौजूद कुछ मिनरल्स कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में सभी जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाएगी। अधिकांश लोगों को कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स का मुख्य सोर्स संतुलित डाइट होता है, केवल पीने का पानी नहीं।

मिथक 2 : आरओ का पानी हर घर के लिए जरूरी होता है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर घर में आरओ वॉटर प्यूरीफायर की जरूरत नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र का पानी कितना साफ है और उसमें किस तरह की अशुद्धियां मौजूद हैं। अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी है, तो हर स्थिति में आरओ की जरूरत नहीं होती। इसलिए पानी की जांच और उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही सही वॉटर प्यूरीफायर का चुनाव करना चाहिए।

मिथक 3: RO का पानी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे जैसे-तैसे स्टोर कर सकते हैं

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, सुरक्षित पानी को भी साफ और ढक्कन वाले कंटेनर में सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। गलत तरीके से स्टोर करने पर पानी दोबारा दूषित हो सकता है। इसलिए पानी को साफ रखने के साथ-साथ उसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है।

मिथक 4: आरओ का पानी गट को कमजोर बना देता है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की उपलब्ध गाइडलाइंस में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि आरओ का पानी सीधे गट को कमजोर बना देता है। गट हेल्थ कई कारणों, जैसे खानपान, फाइबर, लाइफस्टाइल, संक्रमण और दवाओं के इस्तेमाल पर निर्भर करती है। इसलिए इस दावे के समर्थन में फिलहाल पर्याप्त आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

किन परिस्थितियों में आरओ वॉटर प्यूरीफायर की जरूरत पड़ सकती है?

आरओ वॉटर प्यूरीफायर की जरूरत हर घर में नहीं होती। यह आपके इलाके के पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर पानी में TDS बहुत ज्यादा हो या उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, सीसा जैसे हानिकारक तत्व मौजूद हों, तो आरओ प्यूरीफायर उपयोगी हो सकता है।

वहीं, अगर नल का पानी पहले से सुरक्षित है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो हर घर में आरओ लगाना जरूरी नहीं होता। इसलिए पानी की जांच कराने के बाद ही अपनी जरूरत के अनुसार सही वॉटर प्यूरीफायर चुनना बेहतर होता है।

आरओ का पानी पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आरओ वॉटर प्यूरीफायर की नियमित सर्विसिंग कराएं और समय पर उसका फिल्टर बदलवाएं, ताकि पानी साफ और सुरक्षित रहे। आरओ के पानी को हमेशा साफ और ढक्कन वाले बर्तन में रखें और लंबे समय तक खुला न छोड़ें।

शरीर को जरूरी मिनरल्स मुख्य रूप से भोजन से मिलते हैं, इसलिए संतुलित और पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है। अगर आपको पानी की गुणवत्ता या सही वॉटर प्यूरीफायर को लेकर कोई संदेह हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

नेचर लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है भारत के ये बोटेनिकल गार्डन

अगर आप प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो भारत के खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

NBRI

प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने का अपना ही अलग आनंद होता है। यही वजह है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और रेयर पौधों से भरी जगहों की सैर करना पसंद करते हैं। अगर आप भी प्रकृति से प्यार करते हैं, तो बोटेनिकल गार्डन आपके लिए बेहतरीन घूमने की जगह हो सकते हैं। यहां आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई तरह की वनस्पतियों को करीब से देखने का मौका मिलता है।

भारत में कई ऐसे बोटेनिकल गार्डन हैं, जो अपने अनोखे पेड़-पौधों और खूबसूरत माहौल के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जगहें सिर्फ प्रकृति प्रेमियों ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग और शांत माहौल पसंद करने वाले लोगों को भी आकर्षित करती हैं। यहां रंग-बिरंगे फूल, विशाल पेड़ और सलीके से बनाए गए बगीचे यात्रा को यादगार बना देते हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन के बारे में, जहां प्रकृति का अनोखा नजारा देखने को मिलता है, वहां कैसे पहुंचें और घूमने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

भारत के इन 4 खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन को जरूर करें एक्सप्लोर

आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन (हावड़ा, पश्चिम बंगाल)

हावड़ा में स्थित यह भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन में से एक है। यहां हजारों प्रजातियों के पौधे देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ग्रेट बरगद का पेड़ (The Great Banyan Tree) है, जो दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में गिना जाता है।

लालबाग बोटेनिकल गार्डन (बेंगलुरु, कर्नाटक)

बेंगलुरु के मध्य में स्थित लालबाग बोटेनिकल गार्डन करीब 240 एकड़ में फैला हुआ है। यहां रेयर पौधों, रंग-बिरंगे फूलों और ऐतिहासिक ग्लास हाउस को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान लगने वाला फ्लावर शो यहां का प्रमुख आकर्षण है।

एम्प्रेस बोटेनिकल गार्डन (पुणे, महाराष्ट्र)

पुणे में स्थित एम्प्रेस बोटेनिकल गार्डन अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां कई रेयर पेड़-पौधों की प्रजातियां, रंग-बिरंगे फूल और खुले हरे-भरे लॉन देखने को मिलते हैं। प्रकृति प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह बेहतरीन जगह है।

बोटेनिकल गार्डन (लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

लखनऊ स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) का बोटेनिकल गार्डन विभिन्न तरह के पेड़-पौधों और अपने वैज्ञानिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां औषधीय पौधों, सजावटी फूलों और कई रेयर प्रजातियों का संग्रह देखने को मिलता है। पौधों और प्रकृति में रुचि रखने वालों के लिए यह खास आकर्षण है।

इन बोटेनिकल गार्डन तक कैसे पहुंचें और घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है?

इन सभी बोटेनिकल गार्डन तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हावड़ा, बेंगलुरु, पुणे और लखनऊ देश के प्रमुख शहर हैं, जहां नियमित ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से टैक्सी, बस या मेट्रो के जरिए संबंधित बोटेनिकल गार्डन तक पहुंचा जा सकता है।

इन गार्डन को घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और पौधे व फूल भी पूरी खूबसूरती में नजर आते हैं। सुबह या शाम के समय घूमना अधिक आरामदायक रहता है।

बोटेनिकल गार्डन घूमते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

बोटेनिकल गार्डन घूमते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा इधर-उधर न फैलाएं। पौधों, फूलों या पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं और बिना अनुमति उन्हें तोड़ने से बचें। आरामदायक कपड़े और जूते पहनें तथा गर्मी के मौसम में पानी की बोतल, टोपी और सनस्क्रीन साथ रखें।

अगर गार्डन में किसी हिस्से में प्रवेश प्रतिबंधित हो, तो वहां जाने से बचें। फोटोग्राफी से जुड़े नियमों का पालन करें और शांत वातावरण बनाए रखें, ताकि दूसरे पर्यटकों का अनुभव भी सुखद बना रहे।

ग्राहकों की शिकायतें अब होंगी तुरंत हल, वित्तीय संस्थाओं के लोकपालों को मिला नया मंत्र

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के आंतरिक लोकपालों को ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी समाधान करने का निर्देश दिया। तीसरे वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने बार-बार आने वाले मुद्दों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय लागू करने पर जोर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने सोमवार को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं के आंतरिक लोकपालों को ग्राहकों की शिकायतों का सार्थक, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंतरिक लोकपालों को बार-बार आने वाले मुद्दों की पहचान करनी चाहिए।

डिप्टी गवर्नर ने मूल कारण विश्लेषण करने और सुधारात्मक उपाय लागू करने में मदद करने के लिए भी कहा। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित आंतरिक लोकपालों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। एक प्रभावी आंतरिक लोकपाल तंत्र बाहरी शिकायतों को कम करेगा। उन्होंने बोर्डों और वरिष्ठ प्रबंधन से आंतरिक लोकपाल तंत्र को सशक्त बनाने का आग्रह किया।

आंतरिक लोकपाल क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आंतरिक लोकपाल किसी विनियमित संस्था के भीतर ग्राहक शिकायतों की समीक्षा का अंतिम स्वतंत्र स्तर होता है। यह तब काम आता है जब ग्राहक की शिकायत पूरी तरह से हल नहीं होती है। ग्राहक के आरबीआई लोकपाल या किसी अन्य बाहरी मंच से संपर्क करने से पहले यह व्यवस्था काम करती है। यह तंत्र ग्राहकों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद करता है।

सम्मेलन में कौन-कौन शामिल हुए?

इस सम्मेलन में बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और क्रेडिट सूचना कंपनियों सहित विभिन्न विनियमित संस्थाओं के आंतरिक लोकपाल शामिल हुए। इनके साथ प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राहक सेवा के प्रभारी कार्यकारी निदेशक और प्रधान नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। आरबीआई लोकपाल और वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा थे। आरबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी।

शिकायतों के समाधान पर क्या चर्चा हुई?

सम्मेलन के सत्रों में शिकायत निवारण के हालिया विकास पर चर्चा हुई। इसमें नियामक उम्मीदें और आरबीआई लोकपाल की अंतर्दृष्टि शामिल थी। इसका मुख्य ध्यान तेज, उच्च-गुणवत्ता वाले समाधानों पर था। साथ ही, अनावश्यक शिकायतों को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों पर भी जोर दिया गया। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने आंतरिक लोकपाल ढांचे की प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

डेटा सेंटर इंडस्ट्री देगी रोजगार को नई रफ्तार, 2030 तक 1 लाख इंजीनियरों की होगी आवश्यकता

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत का तेजी से बढ़ता डेटा सेंटर उद्योग आने वाले वर्षों में देश के सबसे बड़े रोजगार सृजक क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में करीब 1 लाख कुशल पेशेवरों (स्किल्ड प्रोफेशनल्स) की आवश्यकता होगी।

एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता मौजूदा लगभग 1.5 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से बढ़कर दशक के अंत तक 6.5 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, देश का डेटा सेंटर बाजार 22 अरब डॉलर से अधिक का हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में अब तक 126 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धताएं हो चुकी हैं। यही वजह है कि डेटा सेंटर उद्योग भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में शामिल हो गया है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा संस्थान, उद्योग और नीति-निर्माता मिलकर भविष्य के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार नहीं करते हैं, तो कौशल की कमी (स्किल गैप) इस क्षेत्र की तेज रफ्तार वृद्धि में बड़ी बाधा बन सकती है।

एनएलबी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सचिन अलुग ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि देश के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण का बड़ा अवसर है।

उन्होंने कहा, भारत जिस तेजी से डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड ऑपरेशंस, ऑटोमेशन, पावर सिस्टम और क्रिटिकल फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ पेशेवरों की नई पीढ़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरियां भरने का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने वाले कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के कारण एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, क्लाउड ऑपरेशंस, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, एमएलऑप्स और डेटा सेंटर ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है।

अनुमान है कि आने वाले वर्षों में एआई-आधारित वर्कलोड भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में डेटा सेंटर उद्योग में प्रवेश करने वाले इंजीनियरों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ एक महत्वपूर्ण कौशल बनती जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी कई नई विशेषज्ञ भूमिकाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस इंजीनियर, लिक्विड कूलिंग इंजीनियर, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल फैसिलिटीज इंजीनियर और पावर सिस्टम एक्सपर्ट जैसे पद प्रमुख हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगली पीढ़ी के एआई-संचालित डेटा सेंटरों को उन्नत कूलिंग सिस्टम, बेहतर ऊर्जा प्रबंधन और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इन विशेषज्ञों की मांग आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ने की संभावना है।

होर्मुज का भाव होगा कम! किस प्लान पर काम कर रहे हैं खाड़ी देश

तेहरान, एजेंसी। अमेरिकी और ईरान के बीच जारी जंग और होर्मुज स्ट्रेट में उर्जा सप्लाई की रुकावटों के बीच गल्फ यानी खाड़ी के देश अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। खाड़ी देश अब होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर हुए बिना ज्यादा से ज्यादा तेल सप्लाई की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक पर निर्भरता कम करना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तेहरान के असर को सीमित करना। अमेरिका और ईरान के बीच जंग से पहले दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता था।

ईरान ने होर्मुज का इस्तेमाल करने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना की घोषणा पहले ही कर दी है। इससे उसे अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। ईरान पर सुरक्षित रास्ते के लिए तेल टैंकरों से लाखों डॉलर की मांग करने का आरोप भी लगा है। फिलहाल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इराक ने पहले ही बड़ी पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। यह होर्मुज के बजाय दूसरे रास्तों से तेल ले जाएंगी।

गोल्डमैन सैक्स की विश्लेषक ईकाइ एलेक्जेंड्रा पॉलस के मुताबिक 2027 के अंत तक इतनी पाइपलाइन क्षमता तैयार हो सकती है। UAE की वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन परियोजना अब लगभग आधी पूरी हो चुकी है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायेद ने अधिकारियों को 2027 तक परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया है। एक बार चालू होने के बाद, 252 मील लंबी यह पाइपलाइन मौजूदा फुजैराह पाइपलाइन के साथ-साथ चलेगी और UAE की ज़मीन के रास्ते तेल निर्यात करने की क्षमता को दोगुना करके 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर देगी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि हालिया घटनाओं ने देश की दीर्घकालिक रणनीति को और मज़बूत किया है। उन्होंने कहा अभी भी दुनिया की बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत कम चोक पॉइंट्स यानी संकरे रास्तों से होकर गुज़रती है। ठइसी वजह से UAE ने एक दशक से भी पहले ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने का फ़ैसला किया था जो होर्मुज होर्मुज स्ट्रेट से ना गुजरे। UAE होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के अरब सागर वाले हिस्से में एक बड़े नए पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल की योजना भी बना रहा है। यह इस क्षेत्र में आने वाले सामान के लिए एक और रास्ता देगी, जिसमें स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। यह भविष्य में दुबई के जेबेल अली पोर्ट को टक्कर दे सकती है।

ईराक भी 435 मील लंबी पाइपलाइन पर कर रहा काम

इसके अलावा ईराक ने 435 मील लंबी बसरा-हदीथा पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो आगे चलकर जॉर्डन, सीरिया और तुर्की से जुड़ेगी। इस प्रोजेक्ट से हर दिन 25 लाख (2।5 मिलियन) बैरल तेल के ट्रांसपोर्ट की उम्मीद है। इसके निर्माण का बजट 1।5 अरब डॉलर रखा गया है।

सऊदी अरब भी अपनी पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाना चाहता है

सऊदी अरब भी रेड सी (लाल सागर) तक जाने वाली अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर 90 लाख (9 मिलियन) बैरल प्रतिदिन करने की योजनाओं पर विचार कर रहा है। इस पर अभी शुरुआती बातचीत ही चल रही है।

क्या है खाड़ी देशों का लक्ष्य

खाड़ी देशों का इन सभी कवायदों का लक्ष्य है कि खाड़ी से होने वाले युद्ध-पूर्व तेल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा इस जलडमरूमध्य के बजाय दूसरे रास्तों से भेजा जा सके। 2028 के अंत तक, हर दिन 7।3 मिलियन बैरल तक तेल वैकल्पिक मार्गों से बह सकता है, जिससे खाड़ी से होने वाला लगभग 60 प्रतिशत तेल निर्यात के लिए होर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं होगी।

फिर भी होर्मुज स्ट्रेट पर बनी रहेगी निर्भरता?

विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देश अगर अपनी योजनाओं पर काम कर भी लेते हैं तो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व बना रहेगा। हर दिन लगभग 70 से 90 लाख (7 से 9 मिलियन) बैरल तेल और रिफाइंड उत्पादों का ट्रांसपोर्ट अभी भी इसी जलमार्ग पर निर्भर रहेगा। कुछ नए एक्सपोर्ट रूट रेड सी में स्थिरता पर भी निर्भर करते हैं। यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने हाल ही में बाब अल-मंडेब स्ट्रेट के पास हमले की धमकी दी है। इसका मतलब है कि भले ही खाड़ी देश क्षेत्रीय तेल एक्सपोर्ट पर ईरान के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वे इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे।

30 साल से ज्यादा उम्र के सैनिकों का हार्मोन टेस्ट कराएगी अमेरिकी सरकार, क्या है मकसद?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सरकार 30 साल से अधिक उम्र के सैनिकों का हार्मोन टेस्ट कराएगी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 30 साल से अधिक उम्र के सैनिकों के लिए साल में एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसका मकसद सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन यानी उसके हार्मोन की कमी को दूर करना है, ताकि सैनिक पूरी ताकत और क्षमता से काम कर सकें।

हेगसेथ ने ये भी कहा कि जिन सैनिकों में कमी पाई जाएगी, उन्हें जांच के बाद जरूरत पड़ने पर सैनिकों को 'टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' भी दी जाएगी, जिससे सैनिकों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सही हो, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि विज्ञान भी यह मानता है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक कम होने लगता है।

सैनिकों की हर साल होगी मेडिकल जांच

अमेरिकी रक्षा सचिव के मुताबिक, अब हर साल 30 साल या उससे बड़े अमेरिकी सैनिकों की मेडिकल जांच होगी। इसमें उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मापा जाएगा। अगर किसी सैनिक के शरीर में इस हार्मोन की कमी पाई जाती है, तो वह अपनी मर्जी से 'हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' ले सकता है। 30 साल से कम उम्र के सैनिक भी मांग करके यह जांच करवा सकते हैं।

इस फैसले पर डेमोक्रेट्स ने उठाए सवाल

यह फैसला तब आया है जब अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टोस्टेरोन इलाज से जुड़े कुछ पुराने कड़े नियमों को आसान बनाने की घोषणा की है। हालांकि, इस फैसले पर डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ समय पहले ट्रांसजेंडर सैनिकों के हार्मोन इलाज पर रोक लगा दी थी। विपक्षी नेताओं (समर ली और सीनेटर टैमी डकवर्थ) का कहना है कि जब सरकार आम सैनिकों को हार्मोन बदलने का इलाज दे रही है, तो यह भी एक तरह की 'जेंडर-अफर्मिंग केयर' ही है। फिर ट्रांसजेंडर सैनिकों के लिए अलग नियम क्यों?

भारतीय मुसलमान शख्स पर अमेरिका में जानलेवा हमला, पुलिस का दावा- धर्म की वजह से बनाया निशाना

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक भारतीय शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। खास बात ये है कि युवक को किसी दुश्मनी या लड़ाई झगड़े को लेकर नहीं बल्कि उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया है। हमलावर ने पहले युवक से उसका धर्म पूछा और उसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में भारतीय युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक ये घटना अमेरिका के यूटा में घटी। यूटा के वैली फेयर मॉल में सोमवार दोपहर एक मुस्लिम शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। जिस शख्स पर हमला किया गया उसका नाम सोहेल है और वो भारत का रहने वाला है। सोहेल इस मॉल के कियोस्क में काम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले आरोपी की पहचान 48 वर्षीय पीटर माइकल लार्सन के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में पीटर ने इस बात को कुबूल किया कि उसने पीड़ित पर महज इसलिए हमला किया क्योंकि वो एक मुस्लिम था। उसने ये भी कहा कि वो मुसलमानों को मारना चाहता है।

मुस्लिम होने पर बनाया निशाना

चश्मीदों के मुताबिक पीटर माइकल मॉल में काम कर रहे सोहेल के पास आया और उससे पूछा कि वो कहां से है। इस पर ने बताया कि वो भारत से है और उसका नाम सोहेल है। इसके बाद आरोपी ने सोहेल से पूछा कि क्या वो मुसलमान है, सोहेल ने इसका जवाब हां में दिया। फिर क्या था ये सुनते ही पीटर ने चाकू निकाला और सोहेल पर ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी ने उसे 15 से ज्यादा बार चाकू मारा। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सोहेल की हालत नाजुक

इस हमले में सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सोहेल के शरीर पर चाकू के कई घाव मिले हैं उसका काफी खून बह गया है। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। उसकी कई सर्जरी हो चुकी हैं। पीड़ित के चिकित्सा खर्चों में सहायता के लिए एक GoFundMe पेज भी बनाया गया है।

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

हमले के दौरान वैली फेयर मॉल में मौजूद लोगों ने किसी तरह आरोपी पीटर माइकल को दबोच लिया और उसका चाकू छीन लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।उसे हत्या की कोशिश और हथियार के अवैध इस्तेमाल के आरोपों में सॉल्ट लेक काउंटी जेल भेजा गया है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार लार्सन पहले के एक हिंसक अपराध के मामले में पैरोल पर था। साल 2022 में उसने अपने ही घर में आग लगा दी थी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को उसने गोली मारने की धमकी दी थी। इस दौरान गोलीबारी भी हुई थी। इस मामले में उसे जेल की सजा मिली थी।

टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा, 13 ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, एजेंसी। आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गुरुवार (16 जुलाई) को चार राज्यों में करीब 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश ATS की FIR के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी का यह धनशोधन मामला 2024 में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (यूपी- ATS) की उस FIRर आधारित है, जिसमें एक ऐसे संगठित गिरोह का जिक्र है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ कराने, उनके लिए जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद करने में संलिप्त था।

राज्य पुलिस के साथ समन्वय में ईडी के लखनऊ ऑफिस की टीम द्वारा तलाशी लिए गए स्थानों में नई दिल्ली में बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, महाराष्ट्र में रायगढ़, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाने का काम कर रहा था।

ईडी की जांच में एक बड़े वित्तीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी फंड हासिल किया गया और फिर उसे कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयरिंग ट्रांजैक्शन के जरिए अलग-अलग जगहों पर भेजा गया।जांच में कैश निकासी और छोटी-छोटी रकम अलग-अलग लोगों तक भेजने के भी सुराग मिले हैं।

ईडी अब इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों, फंड के स्रोत और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ED की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

'अब है दो-तिहाई बहुमत': महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर अठावले का बड़ा दावा, कहा- मानसून सत्र में मिलेगा रास्ता

हैदराबाद, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विश्वास व्यक्त किया है कि महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र में संविधान संशोधन विधेयकों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने पराजित कर दिया था।

उन्होंने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि अब एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा, 'परिसीमन हर 30-35 साल में किया जाता है। परिसीमन भी आवश्यक है।'

उन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों से विधेयकों को पारित कराने में अपना समर्थन देने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री ने क्या दावा किया?

महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता, जो भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सदस्यों द्वारा एनडीए का समर्थन करने और डीएमके के कांग्रेस से अलग होने के मद्देनजर इन विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास दो तिहाई बहुमत है। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित हो जाएंगे।'

क्या है पूरा मामला?

17 अप्रैल को संसद के विस्तारित सत्र के दौरान, विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक निचले सदन में हार गया, जिसमें 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में और 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।

शुरू हुई 'रागिनी 3' की शूटिंग, सेट से तमन्ना भाटिया ने साझा की खास तस्वीर

तमन्ना भाटिया की एंट्री 'रागिनी 3' में कंफर्म हो चुकी है। हाल ही में तमन्ना ने इस फिल्म के सेट से पहले दिन की शूटिंग की एक खास तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है।

प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता शशांक घोष 'रागिनी 3' का निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में तमन्ना ने इस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन की एक खास तस्वीर साझा कर फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है।

तमन्ना भाटिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'रागिनी 3' के सेट से एक खास तस्वीर साझा कर फैंस का दिल जीत लिया है। तमन्ना ने 'रागिनी 3' के क्लैप बोर्ड के साथ एक खास तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की है। इस तस्वीर में क्लैप बोर्ड के ऊपर लिखा है- '15.07.26 दिन पहला' यानी इस फिल्म की शूटिंग 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है।

'रागिनी 3' के बारे में

'रागिनी 3' का निर्देशन शशांक घोष करेंगे, जिन्होंने 'वीरे दी वेडिंग' और 'खूबसूरत' जैसी हिट फिल्मों के अलावा 'फ्रेडी' और 'क्विक गन मुरुगन' जैसी लीक से हटकर फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। बाकी स्टार कास्ट की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। इस फिल्म की निर्माता एकता कपूर हैं, जिन्होंने इस फिल्म के पहले के दोनों भागों का भी निर्माण किया है।

'रागिनी' की अब तक की फिल्में

अभी तक एकता कपूर की फिल्म 'रागिनी' के दो भाग रिलीज हो चुके हैं। अब एकता 'रागिनी 3' लेकर आ रही हैं। 'रागिनी 3' आगामी बॉलीवुड हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। इसे 'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग माना जा रहा है। तमन्ना भाटिया के अलावा इस फिल्म में जुनैद खान, नरगिस फाखरी और आयुष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं।

नोलन की 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज, ओपनिंग डे मिस न हो, इसलिए फैन ने टाल दी फैमिली प्लानिंग

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' 18 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज को तैयार है। बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फैंस दिल थाम कर इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' सिर्फ दर्शकों में उत्साह ही नहीं जगा रही, बल्कि लोग इसके लिए अलग-अलग तरीके भी अपना रहे हैं। अमेरिका की एक फैन ने बताया कि उन्होंने अपनी दूसरे बच्चे की प्लानिंग इसलिए टाल दी, ताकि वह फिल्म के ओपनिंग डे की IMAX 70mm स्क्रीनिंग मिस न करें। इससे पता चलता है कि इस फिल्म के लिए फैंस कितनी हद तक जा रहे हैं।

फिल्म को मिस नहीं करना चाहते फैंस

कैलिफोर्निया की 29 साल की एंबर कॉनाघन ने वैरायटी को बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी फैमिली प्लानिंग कुछ समय के लिए टाल दी, ताकि वह 17 जुलाई को 'द ओडिसी' की स्क्रीनिंग देख सकें। एंबर ने कहा, 'मेरी एक दोस्त पिछले साल प्रेग्नेंट हुई थी और उसने मुझसे कहा, 'अब तुम्हें भी अपना दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए।' लेकिन मैंने कहा, 'नहीं, मुझे कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा, नहीं तो यह 'द ओडिसी' के बहुत करीब हो जाएगा।'

दूसरे शहर फिल्म देखने जा रहे दर्शक

एंबर अकेली ऐसी फैन नहीं हैं जो इस फिल्म के लिए अलग तरीके अपना रही हैं। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग 'द ओडिसी' को IMAX 70mm में देखने के लिए दूसरे शहरों तक की फ्लाइट बुक कर रहे हैं। वहीं, कुछ फैंस ने टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट क्रैश और लंबी कतारों का भी सामना किया।

ऐसी है 'द ओडिसी' की कहानी

'द ओडिसी' होमर की 'द ओडिसी' पर आधारित है, जो साहित्य की सबसे महान यात्राओं में से एक है। जहां ओडिसियस घर लौटने के लिए तूफानों, राक्षसों और अशांत समुद्रों से जूझता है। इस फिल्म में मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिनसन, टॉम हॉलैंड, जेंडया, ऐनी हैथवे, चार्लीज थेरॉन और ट्रैविस स्कॉट जैसे सितारे प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। 'द ओडिसी' दुनिया भर में 18 जुलाई को और भारत में एक दिन पहले रिलीज हो रही है।

इमरान हाशमी शैतानी दुनिया में करेंगे वापसी, नई हॉरर फिल्म रूह का हुआ ऐलान, आई पहली झलक

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच उनकी एक और नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। वो एक बार फिर हॉरर जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं। एक्टर जल्द ही फिल्म रूह में नजर आने वाले हैं। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाई है।

मेकर्स ने आज इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ इसका एक डरावना फर्स्ट लुक भी जारी किया है, जिसने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा दिया है। मेकर्स ने 52 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है।रूह का फर्स्ट-लुक टीजर एक दमदार और डरावनी अवाज के साथ शुरू होता है।

इसके बाद वीडियो में हवा में तैरती हुई एक लड़की की झलक देखने को मिलती है। वीडियो में आगे एक हाथ धुंधला सा शीशा साफ करता है, जिसके बाद इमरान हाशमी का चेहरा नजर आता है।और अचानक इमरान हाशमी की आंखें काली हो जाती हैं। इसके बाद फिल्म का टाइटल रूह लिखा नजर आता है।

इमरान हाशमी ने इससे पहले राजः द मिस्ट्री कंटीन्यूज, राज 3, राज रीबूट और एक थी डायन जैसी हॉरर फिल्मों में काम किया है। अब रूह के साथ इमरान एक बार फिर उसी डर और रहस्य से भरी दुनिया में लौट रहे हैं।

मेकर्स ने आगे बताया कि फिल्म अगल साल 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी और ये हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म रूह का निर्देशन मयंक शर्मा कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने मिलकर लिखी है।

आवारापन 2 की बात करें तो इस फिल्म इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी लीड एक्ट्रेस को तौर पर नजर आएंगी। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान को आखिरी बार फिल्म हक में देखा गया था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com